CNEWS सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-192
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, गुरुवार 17 अक्टूबर 2024

आज का विचार

हार मानने से पहले, एक बार और प्रयास करने की सोचो

नायब सैनी आज हरियाणा सीएम की शपथ लेंगे

कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट आई सामने

हरियाणा में नायब सिंह सैनी आज गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह करीब सवा 1 बजे पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मनोहर लाल, 18 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम बीजेपी नेता भी शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि CM हाउस में मंजे डाल रखे हैं। हरियाणा के मेरे परिवारजनों के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे।

मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने चंडीगढ़ पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जीत ने साबित कर दिया है कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जश्न मना रहा है। तीसरी बार सरकार बनाना कोई आसान काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी और पूरे भारत गठबंधन ने हरियाणा चुनाव में हर तरह का नकारात्मक प्रचार किया, लेकिन हरियाणा की जनता ने सभी नकारात्मक प्रचार को खत्म करके मोदी जी के सुशासन पर मुहर लगा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पंचकूला के वाल्मीकि मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि की जयंती है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का काम किया और समाज को एक संदेश दिया। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान वाल्मीकि के चरणों में पूजा करने का अवसर मिला है। मैं उनकी जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि हरियाणा पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने के बाद बुधवार यानी 16 अक्टूबर को बीजेपी ने पंचकूला में भाजपा दफ्तर पंचकमल में विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में पर्यवेक्षक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। बैठक में नायब सैनी को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी के साथ मंत्रिमंडल जानकारी के मुताबिक़ सरकार में इस क्रम पर रहेगी !

2. अनिल विज अम्बाला कैंट , कैबिनेट मंत्री।
3. कृष्ण लाल पंवार इसराना, कैबिनेट मंत्री।
4. राव नरवीर सिंह बादशाहपुर, कैबिनेट मंत्री।
5. महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण, कैबिनेट मंत्री।
6. विपुल गोयल फरीदाबाद, कैबिनेट मंत्री।
7. डॉ अरविंद शर्मा गोहाना, कैबिनेट मंत्री।
8. श्याम सिंह राणा रादौर, राज्य मंत्री।
9. रणवीर सिंह गंगवा बरवाला, राज्य मंत्री।
10. कृष्ण बेदी नरवाना, राज्य मंत्री।
11. श्रुति चौधरी तोशाम, राज्य मंत्री।
12. आरती राव अटेली, राज्य मंत्री।
13. राजेश नागर तिगांव, राज्य मंत्री।
14. गौरव गौतम पलवल, राज्य मंत्री।

सीएम मोहन यादव की छवि अब राष्ट्रीय नेता के रूप में

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि अब राष्ट्रीय नेता के रूप में बन रही है। पार्टी भी लगातार उनकी इमेज बिल्डिंग में लगी है। उन्हें देश के अलग-अलग चुनावी राज्यों में हाल के दिनों में प्रचार के लिए भेजा गया था। अब हरियाणा में गृहमंत्री अमित शाह के साथ उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर पार्टी ने साफ संदेश दिया कि मोहन यादव अब बीजेपी में लंबी रेस के घोड़े हैं। हरियाणा में विधायक दल की मीटिंग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम मोहन यादव भी पहुंचे थे। वहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीएम मोहन यादव कदमताल करते दिख रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि सीएम का कद कैसे बीजेपी में बड़ा हो रहा है। साथ ही पार्टी भी उन्हें उभारने में लगी है। सीएम मोहन यादव को यादवों के नेता के रूप में स्थापित कर बीजेपी यूपी-बिहार के यादवों को साधना चाहती है। सीएम बनने के बाद मोहन यादव सबसे पहले बिहार ही गए थे। वहां यादवों की 17 फीसदी आबादी है। 2025 में वहां विधानसभा के चुनाव हैं। यही स्थिति यूपी में भी है। पार्टी इन दोनों राज्यों में यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि हमने आपके समाज के जमीन से जुड़े नेता को यहां तक पहुंचाया है। वहीं बुधवार को हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी चुने गए। पंचकूला स्थित भाजपा दफ्तर में भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया। भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक में मौजूद रहे।

कमीशन कम होने से भड़क गए एलआईसी के एजेंट, काम बंद करने की चेतावनी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने अपने एजेंटों का कमीशन कम कर दिया है। इसके चलते एलआईसी के एजेंट खफा हैं। कई एजेंट एसोसिएशनने काम बंद करके एलआईसी की ब्रांचों के सामने धरना और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। एलआईसी को सरेंडर वैल्यू नियमों में हुए बदलाव के चलते अपनी कई पॉलिसी के नियम बदलने पड़े हैं। इसकी वजह से कमीशन को भी रीस्ट्रक्चर किया गया है। इस जानकारी के सामने आने के बाद पूरे देश में एजेंटों में गुस्सा है। वे अपनी मांगें न मानने पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। सरेंडर वैल्यू के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हुए हैं। इसके तहत अब पहला प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर भी लोगों का पूरा पैसा डूबेगा नहीं। उन्हें प्रीमियम का कुछ हिस्सा वापस मिल जाएगा। इस कारण से एलआईसी ने कई पॉलिसी के नियमों में बदलाव किया है और एजेंटों का कमीशन भी घटा दिया है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों को लिखे पत्र में डिमांड की है कि वे एलआईसी पर नए नियमों को वापस लेने का दबाव डालें।

रेलवे से रिटायर हुए कर्मियों फिर से जॉब देगी सरकार

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने दिवाली के पहले अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर बताया कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी पर रखा जाएगा। हर जोन के जनरल मैनेजर को यह अधिकार होगा कि वे रिटायर्ड कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के जनरल मैनेजरों को लिखे एक सर्कुलर में बताया कि सुपरवाइजर और स्टाफ की कमी को देखते हुए रेलवे को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बार फिर से नौकरी पर रखने का फैसला किया है। हालांकि, यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब होगी, जिसमें कोई कर्मचारी 2 साल या 65 साल की आयु (जो भी पहले हो) तक ही नौकरी कर सकता है। जानकारी के अनुसार, सर्विस के पूरे पीरियड में उन्हें हर महीने के 1.5 दिनों की पेड लीव दी जा सकती है। हालांकि, एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टी जमा करने की अनुमति नहीं होगी और न ही नियुक्ति बढ़ाए जाने पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही, अनुबंध के खत्म होने के वक्त बची हुई पेड लीव के बदले कोई भुगतान भी हीं किया जाएगा।

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार, नॉन गैजेटेड रेलवे स्टाफ जो कि अपने रिटायरमेंट के समय पे लेवल 1 से पे लेवल 7 तक काम कर रहा हो, उसे उसी लेवल पर फिर से हायर किया जाएगा। यह अधिकार सिर्फ जनरल मैनेजर के पास होगा। हालांकि, दोबारा नौकरी पर रखने से पहले कर्मचारियों का उनके पोस्ट के हिसाब से मेडिकल फिटनेस देखी जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के आखिरी 5 साल में उनके काम को भी रिव्यू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में अब नई 'लेडी ऑफ जस्टिस, आंखों से पट्टी हटी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक बदलाव के तहत, न्याय की देवी 'लेडी ऑफ जस्टिस' की एक नई मूर्ति का अनावरण किया गया है। इस नई मूर्ति ने न्यायिक चेतना में एक प्रगतिशील बदलाव को प्रदर्शित किया है। कांस्य निर्मित इस मूर्ति में पट्टी हट चुकी है और अब वह तलवार के बजाय संविधान को थामे हुए है, जो आधुनिक न्याय के आदर्शों का जीवंत चित्रण है। यह प्रतीकात्मक बदलाव भारत में कानून और न्याय प्रशासन पर एक नए दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। सदियों से, 'लेडी ऑफ जस्टिस' को आंखों पर पट्टी के साथ दिखाया जाता रहा है, जो निष्पक्षता का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि न्याय किसी के पद, धन, या शक्ति के आधार पर भेदभाव नहीं करता। उसकी तलवार अदालत की कानून और व्यवस्था लागू करने की शक्ति को दर्शाती थी। हालांकि, यह नई मूर्ति, जिसे प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा अनुमोदित किया गया है, इन पारंपरिक प्रतीकों से हटकर न्याय की एक अधिक गहरी और विकसित समझ को दर्शाती है।

इस नई मूर्ति को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनते हैं।

सरकारी कंपनी बीईएमएल बनाएगी पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन, दो वर्षों में होगी तैयार

नई दिल्ली। सरकारी स्वामित्व वाली बीईएमएल (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) को दो हाई-स्पीड ट्रेनों की डिजाइनिंग, निर्माण और संचालन के लिए 867 करोड़ रुपएका ठेका मिला है। पहली बार देश में ऐसी स्वदेशी बुलेन ट्रेन का निर्माण होना है, जिसकी अधिकतम गति 250 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बीईएमएल को हाई स्पीड ट्रेन बनाने का ठेका चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) की ओर से दिया गया है। रेल मंत्रालय ने आईसीएफ से दो ऐसी रेलगाड़ियां बनाने को कहा है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल सकें। अब आईसीएफ ने इन रेलगाड़ियों के लिए टेंडर जारी कर काम बीईएमएल को सौंप दिया है। बीईएमएल ने एक्सचेंजों को दी जानकारी में बताया कि इसके प्रत्येक डिब्बे की कीमत 27.86 करोड़ रुपए होगी और पूरा अनुबंध 866.87 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने बताया है कि इस राशि में डिजाइन की लागत, एक बार ट्रेन तैयार करने की लागत, गैर-आवर्ती शुल्क, जिग्स, फिक्सचर, टूलींग और परीक्षण सुविधाओं के लिए किया गया एकमुश्त निवेश शामिल है।

एमपी में अरबपति निकला एक और सरकारी कर्मचारी

लग्जरी कारें..लाखों की 'वेलरी समेत मिला बहुत कुछ...

भोपाल। आय से अधिक संपत्ति के एक बड़े मामले में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने भोपाल के हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में छापेमारी की। टीम ने तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारी रमेश हिंगोरानी के घर और छह ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। इस छापेमारी में अब तक 90 करोड़ की संपत्ति मिलने का खुलासा हुआ है। रमेश हिंगोरानी के निर्मल नर्सरी, लक्ष्मण नगर कॉलोनी स्थित निवास पर लोकायुक्त टीम ने बुधवार सुबह पांच बजे दबिश दी। टीम को लग्जरी कारें, डायमंड-गोल्ड ज्वेलरी और भारी मात्रा में कैश मिला है। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि फिलहाल कार्रवाई जारी है। आरोपी ने सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया था। उसके बेटे पर नाबालिग के दुष्कर्म का भी आरोप लग चुका है। लोकायुक्त टीम ने रमेश हिंगोरानी के बैरागढ़ स्थित बंगले, गांधीनगर स्थित लक्ष्मी देवी विकयोमल सर्राफ हायर सेकेंडरी स्कूल, किरण प्रेरणा स्कूल, मैरिज गार्डन सहित कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की। उसने कई साल पहले सरकारी जमीन पर कब्जा कर शादी गार्डन भी बनाया था। जिला प्रशासन ने इस गार्डन को 2 वर्ष पहले तोड़ दिया था। सूत्र बताते हैं कि हिंगोरानी और उसके बेटों ने सराफा एजुकेशन सोसाइटी के तीन स्कूलों पर कब्जा जमा रखा है। इस गोलमाल के लिए रमेश ने बेटों को स्कूल का संचालक बना रखा है। उसके ऐवज में वह उन्हें मोटी तनख्वाह भी देता है। रमेश के बेटे मोहित हिंगोरानी पर नाबालिग स्कूली बच्ची से दुष्कर्म का मामला भी दर्ज हो चुका है।

सबूत मिलने के बाद डाल दी रेड

बताया जाता है कि लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि सतपुड़ा भवन स्थित शिक्षा सचिवालय के तकनीकी शिक्षा विभाग में जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के पास आय से अधिक संपत्ति है। इस सूचना के बाद लोकायुक्त पुलिस ने इसकी जांच-पड़ताल की। कुछ सबूत मिलने के बाद लोकायुक्त ने 6 टीमें बनाईं और एक साथ आरोपी रमेश के ठिकानों पर रेड डाल दी।

नकदी गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी

जांच में अब तक 70 लाख रुपए की ज्वेलरी, कई लग्जरी कारें, और नकदी बरामद हुई है। नकदी इतनी अधिक है कि उसे गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ीं। लोगाकायुक्त पुलिस की तरफ से जारी बयान में अभी तक करोड़ों रुपए की संपत्ति होने की बात कही गई है। अभी लोकायुक्त पुलिस की ओर से नगदी की गिनती करने की बात कही जा रही है। छापेमारी में हिंगोरानी के पास से क्रेटा और स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी कारें, 1 किलो से अधिक सोना और हीरे की ज्वेलरी भी बरामद हुई। इसके अलावा उनके घर और अन्य ठिकानों से 5 महंगे दोपहिया वाहन भी पाए गए हैं। रमेश हिंगोरानी, उनके बेटे योगेश और नीलेश पर भोपाल के गांधीनगर इलाके में करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उसे बेचने के भी आरोप हैं।

आवश्यकता

प्रदेशो, जिला एवं तहसील स्तर पर एक कंपनी के लिए मार्केटिंग हेतु युवक / युवतियों की योग्यता 10वीं से ग्रेजुएट वेतन 15 हज़ार - 20 हज़ार होगा आगे योग्यता अनुसार

Contact WhatsApp Only, Text Message :

9755996590

बिल्डर खुद खाली कर रहे बेसमेंट, 9 ने हटाए अतिक्रमण

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। नगर निगम ने शहर में बेसमेंट में चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने सभी 22 जोन में बेसमेंट को सील करने और पार्किंग स्थलों को खाली करवाने का अभियान तेज कर दिया है। अब तक 150 से अधिक इमारतों पर कार्रवाई की जा चुकी है और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए व्यस्त क्षेत्रों जैसे जेल रोड पर भी जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसी क्रम में योजना क्र. 54, पीयू-4 में 30 इमारतों को नोटिस दिए गए थे, जिनमें से 9 भवन मालिकों ने स्वयं अपने अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

नगर निगम ने दिया था 10 दिन का समय

पिछले हफ्ते, निगम ने जाहिर सूचना के माध्यम से शहर की सभी इमारतों को 10 दिन का समय दिया था ताकि वे अपने-अपने पार्किंग स्थल को खाली करवा लें। यह समय सीमा इस हफ्ते समाप्त हो रही है, जिसके बाद निगम द्वारा सभी जोनों में एक साथ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत उन इमारतों को सील किया जाएगा जिनके बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जबकि उन्हें पार्किंग के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, फायर फाइटिंग सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले कई अस्पतालों, होस्टलों और इमारतों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। फायर सेफ्टी की कमी गंभीर चिंता का विषय है, और निगम इस संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संपत्ति कर के लिए भी एक्शन लेगा निगम

एबी रोड स्थित शॉपिंग मॉल के पीछे पीयू-4 योजना के अंतर्गत चाय और किराना व्यापारियों को भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन अब वहां अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। प्राधिकरण ने कई बार सर्वे किया है, लेकिन अभी तक लीज निरस्त करने जैसी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ, नगर निगम ने इस क्षेत्र में सार्वजनिक पार्किंग पर अवैध अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को नोटिस थमाए हैं। 30 व्यापारियों को नोटिस दिए गए, जिनमें से 9 ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। निगम का राजस्व अमला भी टैक्स वसूली में सक्रिय है। वार्ड 36 के अंतर्गत आने वाली एक टाउनशिप में लाखों रुपये का संपत्ति कर बकाया होने के कारण 85 प्लॉटों पर कार्रवाई की गई है। यदि संपत्ति कर समय पर जमा नहीं किया गया तो कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

बड़े प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया गया

हाईकोर्ट में हाल ही में एक सुनवाई के दौरान निगम यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि शहर में कितनी ऐसी इमारतें हैं जिनमें अधिभोग प्रमाण पत्र के बिना व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। इसी कारण निगम को 10 दिन की मोहलत के साथ जाहिर सूचना जारी करनी पड़ी, जो इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। इसके बाद निगम बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि, कार्रवाई के दौरान यह भी देखा गया कि कई बड़े प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल और होटलों को छोड़ दिया गया, जबकि कई नए निर्माण पूरी तरह से आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक रूप से किए जा रहे हैं, जहां पार्किंग की कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। यह समस्या आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है, और निगम को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

भाजपा के सदस्यता अभियान में इंदौर जिला देश में तीसरे नंबर पर

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। सक्रिय सदस्यता को भाजपा जिला इंदौर की बैठक बुधवार को भाजपा कार्यालय में हुई। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि सदस्यता अभियान में इंदौर के कार्यकताओं ने इतिहास रच दिया। हमारा जिला पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। अब सक्रिय सदस्यता अभियान में भी संगठन ने जो लक्ष्य दिया है, उसे भी इंदौर के कार्यकर्ता पूरा करेंगे। सक्रिय सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी दिलीप पटौदिया ने कहा- सदस्यता अभियान के दूसरा चरण में मंडल अध्यक्षों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। अब मंडल अध्यक्ष की अहम भूमिका अहम रहेगी कि उसके मंडल में निवासरत जनसंघ के समय से कार्य करने वाले पार्टी का कोई भी सदस्य, पार्टी का सक्रियता से कार्य करने वाला कोई भी कार्यकर्ता सक्रिय सदस्यता से ना चुके इसकी जिम्मेदारी मंडल अध्यक्षों की होगी।

एक-एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है जो 100 प्राथमिक सदस्य नहीं बना पाया है, अभी प्रदेश संगठन ने निर्णय लिया है, की प्राथमिक सदस्यता की लिंक खुली रखी जाएगी, ताकि पार्टी बूथ और मंडल में सक्रियता से कार्य करने वाले कार्यकर्ता अपनी रेफरल आईडी से 100 सदस्य बनाकर सक्रिय सदस्य बन सकते हैं।

31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

जिन कार्यकताओं ने 100 सदस्य बना लिए है, उन्हें पत्रक पर अपने सदस्यों के नाम, नंबर और विधानसभा क्षेत्र लिखकर कार्यालय पर या मंडल अध्यक्षों को जमा करवाकर सक्रिय सदस्यता का फॉर्म भरकर सक्रिय सदस्यता ले सकते हैं। 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा।

पार्टी की ओर से दिया गया है टारगेट

जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कहा कि सदस्यता अभियान में जिले के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और बूथों पर सक्रियता के फलस्वरुप इंदौर जिला पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर रहा है। सक्रिय सदस्यता अभियान में प्रत्येक मंडल से 200 कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनाना है।

संगठन को मजबूत करने का कार्य करें

सक्रिय सदस्यता अभियान सहप्रभारी रवि रावलिया ने कहा कि पहले सक्रिय सदस्यता पंजियों पर होती थी, सक्रिय सदस्यता के लिए संगठन ने रचना तैयार की है, ताकि कोई भी मंडल स्तर पर सक्रियता से कार्य करने वाला कार्यकर्ता पार्टी की सक्रिय सदस्यता से वंचित न रहे, इसलिए मंडल स्तर पर भी संयोजक और सहसंयोजक बनाएं गए है। संगठन की रचना की मंशा अनुरूप कार्य करते हुए संगठन को मजबूत करने का कार्य करें।

बीजेपी नेता करता था पिता को प्रताड़ित, पिता ने संपत्ति से बेदखल

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में भाजपा नेता के परिवार का एक विवाद अब सार्वजनिक हो गया है। इसकी वजह है पिता ने ही अपने नेता पुत्र के खिलाफ जाहिर सूचना जारी कर दी है। इसमें संपत्ति से बेदखल करने की बात लिखी गई है और साथ ही कहा है कि हमारा अब उनसे कोई लेना-देना नहीं है। इंदौर विधानसभा पांच जहां से विधायक महेंद्र हार्डिया है, यहां के मंडल वीर सावरकर के अध्यक्ष अमित सिंह रघुवंशी है। इनके पिता है अजीत सिंह रघुवंशी। पिता अजीत ने ही पुत्र अमित के खिलाफ जाहिर सूचना जारी की है। अमित बीजेपी के युवा मोर्चा के नगर कोषाध्यक्ष पद पर भी है। वहीं पिता भी बीजेपी नेता ही है और वह तिलक मंडल के अध्यक्ष के साथ ही युवा मोर्चे में नगराध्यक्ष पद पर रह चुके हैं।

मानसिक और शारीरिक रूप से दी प्रताड़ना

सार्वजनिक तौर पर जारी की गई जाहिर सूचना में कहा गया है कि मेरे बड़े पुत्र अमित का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। उनके द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इससे समाज में प्रतिष्ठा खराब हो रही है। इसलिए फैसला लिया है कि आज दिनांक के पश्चात मेरे पुत्र अमित सिंह रघुवंशी को हम अपनी जायदाद, सम्पूर्ण संपत्ति व मेरे परिवार से बेदखल करते है। अब उनका मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

उनके द्वार किए गए किसी भी तरह के कार्य, वित्तीय व्यवहार, बैंक लोन, कर्ज से मेरा कोई लेना-देना नहीं होगा। उधर पार्टी का कहन है कि यह उनका पारिवारिक आंतरिक मामला है।

बेटा घर पर विवाद करता ह

इस पूरे मामले को लेकर अमित रघुवंशी के पिता अजित सिंह रघुवंशी का कहना है इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। यह हमारे परिवार का अंदरुनी मामला है। बेटा घर पर विवाद करता है। वह घर छोड़कर चला गया है, उसे हमने बुलाया लेकिन वह आया नहीं। जिसके बाद हमने यह निर्णय लिया है।

बीजेपी ने कहा- कहा यह परिवार का मामला

अमित सिंह रघुवंशी को परिवार से बेदखल करने के मामले में बीजेपी नगर संगठन का कहना है कि यह उनके परिवार का अंदरुनी मामला है। पार्टी संगठन के पास किसी भी प्रकार की अभी तक अमित को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। अगर आगे कुछ शिकायत आती है या अन्य कुछ कारण सामने आते है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता विचार कर उचित निर्णय लेंगे।

हरदा पटाखा फैक्टरी कांड के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल को बेल

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। हरदा में 13 लोगों की मौत के जिम्मेदार पटाखा फैक्टरी के मालिक राजेश अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। किडनी की बीमारी से पीड़ित अग्रवाल ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जमानत के लिए आवेदन लगाया था। अग्रवाल को छह माह बाद फिर सरेंडर करना होगा। पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के बाद आठ माह से अग्रवाल जेल में बंद था। अग्रवाल के अलावा चार अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे। उसकी जमानत के खिलाफ हरदा कलेक्टर रिव्यू पिटिशन दायर करने की तैयारी कर रहे है। आरोपी अग्रवाल के परिजन कोलकता में किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते है। राजेश अग्रवाल किडनी की बीमारी से पीड़ित है। जब उसे गिरफ्तार किया था, तब भी उसने किडनी की बीमारी के बारे में बताया था। गिरफ्तारी के दो माह बाद वह भोपाल के अस्पताल में भर्ती हो गया था। डिस्चार्ज होने के बाद उसे फिर जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करने के साथ यह कहा है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद अगले वर्ष अप्रैल माह तक उसे सरेंडर करना होगा।

पीड़ित परिवारों को नहीं मिला घर

फैक्टरी विस्फोट के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के दस से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। मकान में रहने वाले चार लोगों की मौत भी हुई ती। इसके अलावा 8 अन्य लोग विस्फोट के कारण मृत हुए। टूटे मकानों के लोग आठ माह से आईटीआई बिल्डिंग में बने कैम्प में रह रहे है। उनके आवासों की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है। छह फरवरी को हरदा की फैक्टरी में विस्फोट हुआ था। मलबा आधा किलोमीटर तक उड़ कर गया था।

इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और डेढ़ सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

12 लाख पौधे संभाल रही 50 कर्मचारियों की टीम

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। तीन माह पहले इंदौरवासियों ने एक साथ 12 लाख पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया। उसके बाद सबसे बड़ी चिंता थी उन पौधों की साज-संभाल। पौधारोपण के तीन माह तक अच्छी बारिश में पौधे पनप गए।नगर निगम के 50 कर्मचारियों की टीम पौधों को खाद-पानी देने का काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी गर्मी के मौसम में इन पौधों को संभालना। बारिश के कारण पौधे तो पनप गए, लेकिन साथ में उगी खर-पतवार और जंगली घास भी इन पौधों का पोषण ले रही है और अभी तक उन्हें हटाया नहीं गया है। इंदौर में 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 24 घंटे में 12 लाख पौधे लगाकर इंदौरवासियों ने आसाम का रिकार्ड तोड़ा था। वहां एक दिन में 9.21 लाख पौधे लगाए थे। इन 12 लाख पौधों को पेड़ बनने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन वे पनप जाए, इसके लिए 50 नगर निगम कर्मचारी दिन रात जुटे रहते है। सबसे ज्यादा परेशानी टेकरी पर लगे पौधों को पानी देने की है। वहां पानी से भरे बड़े टैंकर नहीं जा सकते है। वहां दो टैंकर 24 घंटे तैनात रहते है और उनमें बोरिंग के जरिए भरा जाता है। उससे पौधों को पानी डाला जा रहा है। नगर निगम दरोगा राकेश यादव के अनुसार इस सीजन में बारिश अच्छी हुई। अक्टूबर माह में हुई बारिश भी पौधों के लिए फायदेमंद रही।

ठंड के सीजन में भी पौधे और ज्यादा पनप जाएंगे। गर्मी के मौसम में इन पौधों का सबसे ज्यादा ख्याल हमें रखना होगा। टेकरी पर कनेर, चंपा,मधुकामिनी, सप्तपर्णी,कदम,नीम, कचनार,सेमल, पलाश, गुलमोहर, करौंदा,आंवला सहित अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए गए है।

नील गायों से बचाने लिए हो रही फेंसिंग

जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि 12 लाख पौधों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। टेकरी के आसपास नील गायें भी आती है। उनसे पौधों को बचाने के लिए तार फेंसिंग कराई जा रही है। इसके अलावा टेकरी पर चार बोरिंग कराए गए है। फिलहाल टैंकरों से पानी दिया जाता है। अब पाइप लाइन बिछाई जाएगी। दो सालों में पेड़ सिटी फारेस्ट का रुप ले लेंगे।

तीन माह से अधिक अवधि का कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित नहीं रहें

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नामांतरण, बंटवारा, रिकॉर्ड सुधार और सीमांकन जैसे सभी राजस्व मामलों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी मामला तीन माह से अधिक लंबित न रहे। सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर सीमांकन प्रक्रिया को लागू करने पर जोर दिया है। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करने का भी कहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों की संख्या के आधार पर निपटान की समय-सीमा तय की जाए और किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से निरस्त न किया जाए। साथ ही, पेशियों की समयबद्धता और पटवारी रिपोर्ट की शीघ्रता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आधार लिंकिंग और केवाईसी को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके अलावा, राजस्व की बकाया वसूली पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है,

भूतिया पार्टी के बाद डॉक्टरों ने पुराने मेडिकल कॉलेज का किया 'शुद्धिकरण'

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। शहर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में हंगामा मचा हुआ है। कॉलेज कैंपस में बनी 150 साल पुरानी इमारत में कथित रूप से 'हैलोवीन पार्टी' हुई थी। इसके बाद गुस्साए डॉक्टरों ने बुधवार सुबह गंगा जल छिड़ककर 'शुद्धिकरण' किया। कॉलेज प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा है कि उसने इस तरह की किसी पार्टी की अनुमति नहीं दी थी। यह ऐतिहासिक इमारत 'किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल' के नाम से जानी जाती है और 1878 में अंग्रेजों के समय में बनी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और दूसरे डॉक्टरों ने यहां गंगा जल छिड़का है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल रोकड़े ने बताया कि हमें पता चला कि इस ऐतिहासिक इमारत में हाल ही में हैलोवीन पार्टी आयोजित की गई थी। हमने गंगा जल छिड़क कर इस इमारत का शुद्धिकरण किया है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए।

कौन थे पार्टी करने वाले लोग?

बताया जाता है कि जैन सोशल ग्रुप ने कॉलेज के डीन से इमारत को अंदर से देखने की परमिशन मांगी थी। हालांकि उन्हें हॉलोवीन पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कॉलेज के डीन डॉ. संजय दीक्षित ने बताया कि उन्होंने जैन सोशल ग्रुप को इमारत के अंदर देखने की इजाजत दी थी, लेकिन 'हैलोवीन पार्टी' की अनुमति नहीं दी थी। उनका दावा है कि इस तरह की कोई पार्टी आयोजित नहीं की गई थी। हालांकि, वे मामले की जांच कर रहे हैं।

ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते

शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. सुमित शुक्ला ने कहा कि सोशल मीडिया पर आईं तस्वीरों से हमें पता चला कि इस इमारत को हैलोवीन पार्टी के लिए भूतिया भवन के रूप में चित्रित किया गया था। हम ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि यह इमारत चिकित्सा क्षेत्र की धरोहर है और गुजरे दौर में कई बड़े चिकित्सकों ने इसमें पढ़ाई की थी। डॉ. शुक्ला इस कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं। उन्होंने इस इमारत के जीर्णोद्धार की बात कही है। उनका मानना है कि यहां इंदौर के चिकित्सा इतिहास से जुड़ी चीजों को सहेज कर रखा जाना चाहिए।

एलुमनाई को मिले रखरखाव

एमजीएम एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. संजय लोंढे ने कहा कि मेडिकल स्कूल बिल्डिंग में अंग्रेजी मानसिकता वाले एक समूह ने हैलोवीन पार्टी/भुतहा पार्टी मनाई। इस घटना का सख्त विरोध किया जाए। इस इमारत की रखरखाव एलुमनाई एसोसिएशन को दिया जाए. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भविष्य में शिक्षा से जुड़े ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को विशेष संरक्षण दिया जाए।

एमटीए ने बताया चिकित्सक बिरादरी का अपमान

एमटीए की ओर से कहा गया कि यह पार्टी एक तरह से ऐतिहासिक बिल्डिंग और चिकित्सक बिरादरी का अपमान है। किंग एडवर्ड हाल हमारी विरासत है।

सिंगल कॉलम

फर्जी प्रवेश पत्र लेकर आर्मी का एग्जाम देने पहुंची युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार

भोपाल। शाहजहानाबाद पुलिस ने झारखंड की एक युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। युवती पर आरोप है कि युवती फर्जी प्रवेश पत्र लेकर आर्मी में भर्ती होने के लिए पहुंची थी। इस मामले की शिकायत सुल्तानिया इन्फैंट्री लाइन्स शाहजहानाबाद की तरफ से की गई थी। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को सुल्तानिया इन्फैंट्री लाइन्स में आर्मी भर्ती परीक्षा का दूसरा फेज चल रहा था। प्रवेश पत्र चेक करने के दौरान शंका होने पर दो युवतियों रुपा और रीमा को पकड़ा। दोनों के प्रवेश पत्र पर फोटो, नाम, पता अलग-अलग था। जबकि रोल नंबर एक जैसा था। जब आर्मी पोर्टल के साइबर सेल में पड़ताल की तो मालूम हुआ कि रीमा का प्रवेश पत्र सही है। जबकि रुपा ने फर्जी प्रवेश पत्र बनवाया है। रुपा से पूछताछ की तो उसने बताया कि 21 अप्रैल को पटना में आर्मी भर्ती परीक्षा में भी बैठी थी। पुलिस ने आरोपी रुपा भारती (23) झारखंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव आज से, 4 राज्यों के छात्र पहुंचेंगे

भोपाल। भोपाल के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय युवा महोत्सव का आयोजन 17 से 19 अक्टूबर तक किया जाना है। जिसमें सांस्कृतिक, शैक्षिक और खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर के सह निर्देशक प्रो. नीलाभ तिवारी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत के अलग-अलग राज्यों के 9 संस्थाओं के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। ये छात्र अपनी संस्था से जीत कर यहां प्रतिस्पर्धा करने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शोभायात्रा और फ्लैग होस्टिंग से कार्यक्रम की शुरूआत की जाएगी। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगु भाई पटेल शामिल होंगे। निर्देशक पांडेय ने कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक विकास भी करना बताया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने बुंदेली रामायण के गायक डॉ. आनंदी लाल कुर्मी को आमंत्रित किया है। साथ ही संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रो. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी और पद्मश्री और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति प्रो. अभिराज राजेंद्र मिश्र जैसे विद्वान भी शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के लिए बच्चों के रुकने की व्यवस्था परिसर स्थित हॉस्टल में की गई है।

ईशा फाउंडेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ओबीसी महासभा...

भोपाल। सद्गुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन के विवाद में अब ओबीसी महासभा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र कुशवाह ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है। ओबीसी महासभा ने कहा है कि ईशा फाउंडेशन समेत सभी धर्मों के धार्मिक संस्थानों में 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक शोषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है। इसमें धार्मिक संस्थानों में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के सख्त पालन की मांग की गई है। यह आवेदन ओबीसी महासभा और दो अन्य लोगों ने दायर किया है। इसमें ईशा फाउंडेशन पर आरोप लगाए गए हैं कि ईशा फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संगठन है, जिसका नेतृत्व सद्गुरु जग्गी वासुदेव करते हैं, लेकिन एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने दावा किया है कि उनकी बेटियों को इस आध्यात्मिक लीडर (जग्गी वासुदेव) ने प्रभावित किया है। यह आवेदन अधिवक्ता वरुण ठाकुर द्वारा दायर किया गया है।

कांग्रेस ने नेता विपक्ष उमंग सिंघार को बनाया महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक

भोपाल। कांग्रेस ने एमपी के नेता विपक्ष उमंग सिंघार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता सिंघार, जो वर्तमान में धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं, को महाराष्ट्र के विदर्भ संभाग के अंतर्गत आने वाले अमरावती और नागपुर जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों भूपेश बघेल (छत्तीसगढ़) और चरणजीत सिंह चन्नी (पंजाब) के साथ काम करेंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ संभाग के अमरावती और नागपुर दोनों जिले मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों से सीमा साझा करते हैं।

विजयपुर- बुधनी को लेकर कांग्रेस में रायशुमारी, बुधनी में भाजपा की मशक्कत

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश में खाली हुई दो विधानसभा सीटों विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव का बिगुल बच चुका है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को तारीखों की घोषणा कर दी है। अब दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी को लेकर घमासान मचा हुआ है। जहां बीजेपी एक सीट विजयपुर पर अपना प्रत्याशी तय कर चुकी है वहीं कांग्रेस को अभी दोनों ही सीटों में प्रत्याशी की तलाश कर रही है। कांग्रेस छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद इन दोनों सीटों पर विशेष फोकस कर रही है। प्रत्याशी के चयन में इस बार कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नेताओं से रायशुमारी कर रही है और इसी आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। कांग्रेस के रायशुमारी में दोनों सीटों पर कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने दोनों सीटों पर चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जारी चुनावी कार्यक्रम के अनुसार दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वही चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 18 अक्टूबर को गजट अधिसूचना जारी होगी। जिसके बाद से चुनावी प्रक्रिया जारी हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी। वही 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है।

जीतू पटवारी सहित कई नेताओं ने संभाला मोर्चा

विजयपुर और बुधनी सीट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। दोंनों सीटों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल कांग्रेस दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। दोनों सीटों पर कांग्रेस की साख दाव पर है।

विजयपुर में 'आदिवासी' दाव लगा सकती है कांग्रेस

कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे रामनिवास रावत के कांग्रेस छोड़ने के बाद खाली हुई विजयपुर सीट कांग्रेस के लिए बहुत ही खास मानी जा रही है। जहां विजयपुर से बीजेपी ने रामनिवास रावत को उम्मीदवार बनाया है।

वही कांग्रेस की बात करे तो कई संभावित उम्मीदवारों के नाम समाने आए है। माना जा रहा है कि कांग्रेस विजयपुर से आदिवासी या ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है। विजयपुर सीट से कांग्रेस से आदिवासी नेता छोटेलाल सेंमरिया का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वही कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा, पूर्व जनपद अध्यक्ष रमेश आदिवासी, और पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा प्रबल दावेदार माने जा रहे है। इसके अलावा पूर्व कलेक्टर पन्ना लाल सोलंकी का नाम भी चर्चा में बना हुआ है।

बुधनी से पांच नाम की प्रबल दावेदारी पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। जहां बीजेपी इस सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी बता रही है वहीं कांग्रेस शिवराज के जाने के बाद जीत की उम्मीद लगाए हुए है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जहां बीजेपी के कई नामों की चर्चा है, वहीं कांग्रेस के रायशुमारी में भी कई नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इस सीट से कांग्रेस से पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष महेश राजपूत, अजय पटेल, प्रवेश प्रदेश प्रवक्ता आनंद जाट और कमलेश यादव का नाम प्रबल दावेदारों की सूची सामने आ रहा है। दोनों सीटों पर प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार कर कांग्रेस आलाकमान को भेजा जाएगा। दिल्ली से मुहर लगने के बाद उम्मीदवारों का ऐलान संभव होगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अभी बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार कर रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस अपने पत्ते खेलेगी।

विजयपुर में कांग्रेस और भाजपा का कड़ा मुकाबला

विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने 1990 से 2018 तक छह बार जीत दर्ज की है। रामनिवास रावत, जो कांग्रेस के प्रमुख चेहरे थे, भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब कांग्रेस एक मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार की तलाश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने कार्यकताओं से सुझाव लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदिवासी वोट बैंक इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाता है और कांग्रेस इसे ध्यान में रखते हुए अपना उम्मीदवार तय करने की योजना बना रही है। वहीं, भाजपा के भीतर रामनिवास रावत को टिकट देने से गुटबाजी और असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, जो पार्टी की मुसीबत बढ़ा सकती है।

बुधनी में भाजपा का किला और कांग्रेस की चुनौती

बुधनी विधानसभा सीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाती है। यहां भाजपा अपनी जीत को लगभग तय मान रही है। हालांकि, पार्टी के सामने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह, और शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सहित कई दावेदारों के नाम आए हैं। अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी के चयन पर अंतिम निर्णय करेगा। कांग्रेस की स्थिति यहां कमजोर है, क्योंकि पिछले तीन दशकों में केवल दो बार (1993 और 1998) यहां जीत हासिल कर पाई है। इस बार कांग्रेस फिर से नए चेहरे को मौका देने की योजना बना रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को चुनौती देना उनके लिए कठिन होगा।

दोनों पार्टियों का जोरदार प्रचार

दोनों पार्टियों ने विजयपुर और बुधनी में पहले से ही चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इन क्षेत्रों में बड़े कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और जनता को रिझाने के लिए रोड शो भी किए। कांग्रेस भी अपने स्तर पर सक्रिय है और क्षेत्र में यात्राएं कर पार्टी कार्यकताओं से रायशुमारी कर रही है।

राहुल संग मीटिंग... और फिर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने को तैयार कमलनाथ

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीते कुछ समय से राजनीतिक तौर पर कम सक्रिय हैं, मगर अब उनके फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। कमलनाथ के लिए यह अनुमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी दिल्ली में हुई मुलाकात के आधार पर लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी और कमलनाथ की इस मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। साथ ही यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि कमलनाथ की राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर सक्रियता बढ़ेगी और आगामी चुनाव में वह बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजनीति से मध्यप्रदेश की ओर रुख किया था। उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। कांग्रेस सत्ता में महज 15 महीने रही। आपसी खींचतान के चलते सत्ता हाथ से खिसक गई और भाजपा की फिर सत्ता में वापसी हो गई। उसके बाद से कमलनाथ का दायरा लगातार सिमटता गया और अभी में उनकी ज्यादा सक्रियता छिंदवाड़ा तक सीमित है।

कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ खुद छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, वहीं उनके करीबी अमरवाड़ा से विधायक रहे कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। अभी हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने कमलनाथ का राजनीतिक तौर पर कोई उपयोग नहीं किया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के अलावा उप चुनाव भी होने वाले हैं। मध्यप्रदेश के दो विधानसभा क्षेत्र बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कमलनाथ के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे न केवल मुलाकात की, बल्कि दो घंटे तक दोनों साथ भी रहे।

महत्वपूर्ण मानी जा रही मुलाकात

राहुल और कमलनाथ की इस मुलाकात को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीति के जानकारों का मानना है कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और वहां के कई इलाकों में कमलनाथ का प्रभाव है और सियासी तौर पर दखलअंदाजी भी है। इतना ही नहीं महाराष्ट्र के औद्योगिक घरानों से भी कमलनाथ की नजदीकियां है। कांग्रेस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के प्रभाव का उपयोग करना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी ने उनसे लंबी चर्चा की है।

दिग्विजय से दूरी बना रही कांग्रेस

वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश से ही नाता रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पार्टी ने पूरी तरह किनारे कर दिया है और उनका न तो जम्मू कश्मीर व हरियाणा के चुनाव में कोई उपयोग किया गया और अब संभावना यही है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी पार्टी उन्हें दूर ही रखने वाली है।

बीना विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे पर असमंजस

विधानसभा अध्यक्ष जल्द कर सकते है सुनवाई

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे द्वारा कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करने और आधिकारिक रूप से कांग्रेस छोड़ने की घोषणा के बावजूद, उन्होंने अब तक अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है। अब निर्मला सप्रे ने 10 अक्टूबर को विधानसभा में अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वॉइन की है। उनका यह बयान दलबदल कानून के तहत सदस्यता निरस्त करने के जवाब में आया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से बगावत करते हुए भाजपा के पक्ष में प्रचार किया था और सार्वजनिक तौर पर पार्टी बदलने का ऐलान भी किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ कई जनसभाओं में भाग लिया, लेकिन अभी तक अपनी विधायकी भी नहीं छोड़ी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 5 जुलाई को दलबदल कानून के तहत निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। सिंघार का तर्क था कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा के पक्ष में प्रचार किया है, जिससे उनकी सदस्यता को निरस्त किया जाना चाहिए। अब यह मामला विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, जो जल्द इस मामले में सुनवाई कर सकते है। इस दौरान कांग्रेस से दलबदल के सबूत पेश करने की मांग की जा सकती है। यदि इस मुद्दे पर निर्णय में देरी हुई तो कांग्रेस इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, स्पीकर को किसी अयोग्यता याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय करना आवश्यक है। इस मामले में जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय आने की उम्मीद है।

चार साल की मासूम से ट्यूशन टीचर ने की अश्लील हरकत

भोपाल। राजधानी भोपाल को शर्मशार करने वाली फिर एक बड़ी घटना समाने आई है। इस बार चार साल की मासूम बच्ची के साथ सोहेल नाम के युवक ने दरिंदगी की है। आरोपी मासूम को ट्यूशन पढ़ता है। घटना एक दिन पहले की बताई जा रही है। हिंदू संगठन के कार्यकताओं ने बुधवार सुबह बागसेवनिया थाने पहुंचकर हंगामा किया, इसके बाद पुलिस प्रकरण दर्ज कर रही है। जानकारी के अनुसार, चार साल की मासूम बागसेवनिया थाना क्षेत्र में रहती है। उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं। मंगलवर देर शाम चार साल की मासूम के साथ सोहेल नाम के युवक ने दरिंदगी की है। आरोपी मासूम को ट्यूशन पढ़ता था। दरिंदे ने मासूम को बहला-फुसलाकर ले गया और मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया। मासूम के प्राइवेट पार्ट में खरोंच के निशान मिले हैं। रात में मासूम के परिजनों को घटना का पता चला। बुधवार दोपहर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकताओं को जब सूचना मिली तो वे पीड़ित पक्ष को लेकर थाने पहुंच और मामला दर्ज कराने को कहा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 अक्टूबर को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करेंगे। भोपाल में 21 हजार से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं। इनमें अकेले नगर निगम की ही 5 हजार शिकायतें हैं। ऐसे में अब पूरा फोकस निराकरण पर है। इसे लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह अफसरों की बैठक भी ले चुके हैं। वहीं, जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह को विभागवार समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल में 100 दिन पुरानी शिकायतों को निपटाने पर ज्यादा जोर है। ताकि, शिकायतों का आंकड़ा कम हो सके। मंगलवार के बाद बुधवार को भी अफसरों की मीटिंग हुई।

बच्चों और माताओं की मृत्यु दर को लेकर चिंता, बदलेगा सिस्टम

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। प्रदेश में नवजात बच्चों और प्रसव के समय माताओं की मृत्यु के आंकड़े जुटाने के लिए राज्य सरकार नए सिरे से काम करेगी। सरकार उन कारणों की तलाश भी करना चाहती है कि आखिर किन वजहों से पैदा होने वाले बच्चे या जन्म देने वाली मां की मृत्यु हो गई है। उसे समय पर ट्रिटमैंट नहीं मिला या फिर गर्भवती माता के अस्पताल तक पहुंचने में सड़क, वाहन या अन्य किसी तरह की दिक्कत कारण बनी है। यह भी पता करने का काम होगा कि जिस माता की या उसके बच्चे की मृत्यु हुई है उसकी गर्भकाल के दौरान अस्पतालों में उचित जांच हुई है या नहीं कराई गई है। इसी को लेकर राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को एक दिन की कार्यशाला यूनिसेफ के सहयोग से हुई। इस कार्यशाला में प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर देने की जरूरत है। इससे बाल केंद्रित नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रणाली सार्वभौमिक बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा के लिये एक बड़ा आधार है। केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार देश के सभी जन्म और मृत्यु को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करने के प्रयासों में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) की कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है। कार्यशाला का उद्देश्य बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा के लिएसिविल रजिस्ट्रेशन की क्षमता को मजबूत करना है। कार्यशाला में यूनिसेफ की पूजा सिंह और पीयूष एंथनी वर्चुअली शामिल हुए। कार्यशाला में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, जनजातीय वर्ग और महिला बाल विकास के अधिकारियों ने भागीदारी की। इस दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन नियम 2023 पर जनगणना विभाग द्वारा चर्चा की गई। आयुक्त योजना एवं सांख्यिकी विभाग ऋषि गर्ग, अध्यक्ष राज्य सांख्यिकी आयोग प्रवीण श्रीवास्तव, आयुक्त जनगणना भावना वालिम्बे, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार सिविल रजिस्ट्रेशन आरजी मित्रा एवं उर्वशी कौशिक यूनिसेफ नई दिल्ली ने इस दौरान अपने विचार रखे। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर भी चर्चा की गई। मध्यप्रदेश में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर चिंता का विषय बनी हुई है, भले ही राज्य इस मुद्दे में देश में पहले स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया हो। राज्य में प्रति एक हजार जन्मों पर लगभग 35 नवजात एक माह तक जीवित नहीं रह पाते हैं। हालाँकि, अलीराजपुर जिले में इस आंकड़े में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन खरगोन, बड़वानी, अनूपपुर और शिवपुरी जैसे जिलों में यह दर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। नवजात शिशुओं की उच्च मृत्यु दर के पीछे प्रमुख कारणों में इन्फेक्शन, प्री-टर्म डिलीवरी (समय से पूर्व जन्म), अंडरवेट (कम वजन), और बर्थ एस्फिक्सिया (जन्म के समय श्वास न लेना) शामिल हैं। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि नवजात शिशुओं को संक्रमण मुख्य रूप से डिलीवरी के दौरान लगता है, न कि मां से जैसा कि सामान्य धारणा है। इसके अलावा, सही देखभाल और प्री-मैच्योर शिशुओं की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

सम्पादकीय

सांप्रदायिक टकराव से देश की प्रतिष्ठा कलंकित होगी

बेशक सरकार किसी भी दल की रही हो! संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि अमुक मुसलमानों का इलाका है, तो ये हिंदू, सिख, ईसाई आदि के इलाके हैं? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिन मोहल्लों में मुस्लिम आबादी रहती है, प्रशासन उन्हें 'संवेदनशील' घोषित करता है, जबकि गैर-मुस्लिम क्षेत्रों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मुसलमान संवेदनशीलता के आधार पर नाजुक इलाके क्यों हैं? दरअसल देश को इलाकों और मोहल्लों में बांटा नहीं जा सकता।

जब भी हिंदू देवी-देवता की प्रतिमा की विसर्जन या शोभा-यात्रा निकलती है, तो वह नफरत, अराजकता, वैमनस्य और हिंसा में तबदील क्यों हो जाती है? कई बार हत्याएं भी कर दी जाती हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। अन्य कोई मजहबी जुलूस या मौका हो, तो हिंदू उस पर प्रहार नहीं करते। उसमें रोड़ा नहीं अटकाते। यहां तक कि हिंदुओं ने मस्जिद से की जाने वाली अजान पर भी सांप्रदायिक आपत्ति नहीं जताई है। शोभा-यात्रा निकालने की अपनी शोभा है। अन्य संप्रदायों को उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धार्मिक आजादी का मौलिक अधिकार भी हमें दिया गया है। फिर हिंसा और हत्याओं की क्या वजूहात हो सकती हैं? कई बार यह सवाल उठ चुका है कि अचानक एक भीड़ कहां से उमड़ आती है? छतों से पथराव कैसे होने लगता है? ये छोटे-बड़े पत्थर कहां से, किस तरह इकट्ठा किए जाते हैं? कुछ शहरों, कस्बों में अचानक तलवारें भी चमकने लगती हैं। तलवारें, डंडे और हथियार कहां से आते हैं? कौन उनकी सप्लाई करता है? क्या पत्थरबाजी, दंगे, खून-खराबे की कोई पूर्व नियोजित साजिश तैयार की जाती है? तो साजिशकार कौन हैं? सिर्फ उप्र के बहराइच में ही सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी, तोड़-फोड़ नहीं हुई है। बहराइच को छावनी में तब्दील करना पड़ा। करीब 60 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया और 11 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। उप्र के कई इलाकों में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता रहा है। फिलहाल बहराइच जैसे हालात तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के शहरों और कस्बों में भी पैदा किए गए हैं। सांप्रदायिक हिंसा, दंगे अपने आप ही नहीं भडकते, उन्हें सुलगाया और फैलाया जाता है। भारत में दंगों के काले इतिहास मौजूद हैं। दंगे औसतन सभी राज्यों में होते रहे हैं। उनके असंख्य उदाहरण भी मौजूद हैं। बेशक सरकार किसी भी दल की रही हो! संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि अमुक मुसलमानों का इलाका है, तो ये हिंदू, सिख, ईसाई आदि के इलाके हैं? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिन मोहल्लों में मुस्लिम आबादी रहती है, प्रशासन उन्हें 'संवेदनशील' घोषित करता है, जबकि गैर-मुस्लिम क्षेत्रों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मुसलमान संवेदनशीलता के आधार पर नाजुक इलाके क्यों हैं? दरअसल देश को इलाकों और मोहल्लों में बांटा नहीं जा सकता। इस बार भी आपत्ति की गई कि शोभा-यात्रा मस्जिद के सामने से क्यों गुजरी? क्या यह कानूनन अपराध है या कोई प्रतिबंध लगा रखा है? किसी मुस्लिम की छत से 'हरा झंडा' उतारा गया और उसकी जगह 'भगवा झंडा' लहराया गया, यह अनैतिक हरकत है। इसका कोई औचित्य भी नहीं है। यह घोर सांप्रदायिक है। अवैध कब्जे की एक हरकत है। यदि ऐसी हरकत कर भी दी गई, तो गोली मार कर एक इनसानी हत्या करने की नौबत क्यों आई? जिस हिंदू नौजवान को मार दिया गया, उसकी शादी मात्र दो माह पहले ही हुई थी। किसी औरत को इस कदर विधवा कर देना क्या 'मजहबी प्रावधान' है? जाहिर है कि अलग-अलग समुदायों के लोगों के भीतर नफरत और उन्माद भरे हैं। दूसरी तरफ, यदि शोभा-यात्रा के दौरान उग्रता, हुड़दंग, अभद्र शोर, भडकाऊ नारेबाजी की जाती है, तो वह धार्मिक यात्रा भी बेमानी है। बहराइच या अन्य राज्यों के शहरों में जो नफरती टकराव हुए, वे वाकई अपराध हैं, लेकिन क्या दंगों की भीड़ को कभी सजा दी गई है? कहा जा रहा है कि बीते चार महीने के दौरान ही देश का माहौल बदल गया और आदमी दूसरे को मरने-काटने पर आमादा है। इसका बुनियादी कारण क्या है? चार महीने में देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचे में ऐसा कौनसा बदलाव आया है कि इनसान हत्या पर उतारू है। भारत तो अपनी सहिष्णुता, सौहार्द, समभाव के लिए विश्व विख्यात रहा है।

एआई की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए युवाओं को

युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि सूचनाओं की तरह सत्य भी एक बेहद पेचीदा मसला है। इस अर्थ में अगर देखा जाए तो सत्य की तह तक पहुंचाना और सत्य का ज्ञान प्राप्त करना आज के युग में कितना कठिन होता जा रहा है।अब तक हम बात-विचार को, सुनने -गुनने को, विचारों के आदान-प्रदान के जरिये एक दूसरे से सीखते -सीखाते रहे हैं। अब अगर बातचीत की भी कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, जैसा कि युवाल नोआ हरारी दावा कर रहे हैं। तब यह बेहद जरूरी है कि अभी से हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आने वाली पीढ़ी को तैयार करें।

सन् 1871 में जॉन रस्किन मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक पत्रिका निकलते थे। इस पत्रिका की तारीफ टालस्टाय ने भी की थी और बाद में महात्मा गांधी ने भी इस पत्रिका को खोजकर पढ़ा था। रस्किन की राय है कि वही शिक्षा लेनी चाहिए और वही शिक्षा दरअसल शिक्षा है- जो आत्मा का ज्ञान कराए। मनुष्य मात्र को बचपन से यह जानना चाहिए कि साफ हवा, स्वच्छ पानी और साफ-सुथरी मिट्टी किसे कहते हैं। इन्हें किस तरह रखा जाए और कैसे उपयोग किया जाए? यह बुनियादी सवाल है।

दरअसल, इस मुद्दे पर हर दौर में चर्चा होनी चाहिए। हमें सबक लेना चाहिए कि औद्योगिक विकास के अब तक दौर में हमने इन प्रकृतिक धरोहरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया है? शिक्षा के विषय में बौध दर्शन के विद्वान आचार्य रिनपोछे सवाल करते है कि क्या हमारी मौजूद शिक्षा व्यवस्था में -प्रज्ञा शील और समाधि के लिए कोई स्थान है ? मतलब विवेक, नैतिकता और संसार के बंधनों से मुक्ति के उपायों की कोई गुंजाइश आज की शिक्षा से हम प्राप्त कर सकते हैं ?

यह सवाल इस लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ऐसे समय में हर चीज की कीमत लगाई जा रही है, उसे पण्य वस्तु मानकर खरीद-फरोख्त के लिए अवसरों की तलाश की जा रही है। तब शिक्षा के क्षेत्र में भी यही फॉर्मूला अपनाया रहा हो, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं। एक अनुमान के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये 2035 तक हम विभिन्न क्षेत्रों से अपनी अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर योगदान की संभावना तलाशने में लगे हैं। इनमें स्कूलों-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से लेकर वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग, सरकारी कामकाज, और आटोमेशन की वजह हर क्षेत्र में छंटनी और नौकरियों की सिलेक्सन की प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं।

विश्व विख्यात इतिहासकार युवाल नोआ हरारी दावा करते हैं कि 2034 तक 'अलगोरिदम' और 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' हर क्षेत्र में दुनिया को संचालित करने की स्थिति में आ जाएंगे। सवाल है कि तब हमारे स्कूल के उस 'दुखहरन मास्टर साहब' का क्या होगा, जिसकी चर्चा जन कवि नागार्जुन अपनी एक कविता में करते हैं और उस स्थिति से हमें रुबरु कराते हैं, जो आज भी हमारे गांवों की हकीकत है -

फटी भीत है छत छूती है, आले पर बिस्तुईया नाचे।
बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट- मिनट में पांच तमाचे,
इस तरह दुखहरन मास्टर गढ़ता है, आदमी के सांचे।।

जब आदमी के गढ़ने के सांचे 'अलगोरिदम' और 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' के हवाले होगा तो फिर 'दुखहरन मास्टर साहब' जैसों की सेवा तो समाप्त ही समझें। क्योंकि इस तकनीक को समझने के पहले उन जैसे मास्टर साहबों का दम निकल जाएगा। इस कृत्रिम बौद्धिक मशीन के जन्मदाता एलन टयूरिंग हैं। 1950 में एलेन टयूरिंग ने एक ऐसा कम्प्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जो आदमी की तरह सोच सकता था। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा करते जॉन मैकार्थी कहते है कि-

कृत्रिम बौद्धिकता बौद्धिक मशीन बनाने का एक विज्ञान है। इसके जरिये हर तरह की सीखने की कला और बौद्धिक स्वरूप को मशीन के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। इस तकनीक का शिक्षा के क्षेत्र में आने का तात्कालिक असर यह होगा की क्लास रूम में अब बौद्धिक आदान-प्रदान का माध्यम अध्यापक के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा,जो दूरस्थ शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव के साथ-साथ क्लासरूम के स्वरूप को भी पूरी तरह बदल देगा। यह कृत्रिम बौद्धिक मशीन देर-सवेर भारत में भी शिक्षा का माध्यम तो बनेगी ही। पर सवाल है कि क्या गांवों में अभी उस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर या ऐसी तकनीक से लैस प्राथमिक स्तर पर मास्टर साहब उपलब्ध हैं? हम तकनीकी विकास के हर क्षेत्र में नित नई उड़ान भर रहे हैं।

उम्मीद करना चाहिए कि शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। दावा किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अध्ययन के दौरान छात्रों के हर तरह की मुश्किलों को आसान करने का एक प्लेटफॉर्म होगा। यह हर छात्र के खूबियों और खामियों को डेटा की सटीक व्याख्या के जरिये समाधान करने का सक्षम है। यह किसी छात्र की पसंदीदा और नापसंदगी वाले टॉपिक को समझाने और तदनुरूप उनकी वरीयताएं तय करने की योग्यता भी इसे प्राप्त है। इससे छात्रों को अपने विषय को समझने और अपनी अवधारणा स्पष्ट करने में भी आसानी होगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मौजूदगी से भविष्य में ऐसे और कई चमत्कारिक परिवर्तन आने की संभावना हैं, जिनकी अभी तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। यह एक तरह से दुधारी तलवार वाली तकनीक है। इसलिए उन खतरों से वाकिफ होना भी उतना ही जरूरी है। विश्व विख्यात इतिहासकार युवाल नोआ हरारी अपनी हाल में प्रकाशित पुस्तक नेक्सस में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्यों के हाथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में सामूहिक संहार का एक हथियार हाथ लग गया है। इस पुस्तक में युवाल नोआ हरारी ने पाषाण काल से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग तक मनुष्यों द्वारा सूचना के तैयार किए गए नेटवर्क उन्होंने अपने अब तक के अध्ययन और अनुभवों के जरिये अभिव्यक्त किया है।

मानवीय सभ्यता के विकास में भाषा का प्रचलन शुरू होने के बाद सूचनाओं के आदान-प्रदान, बात-विचार और व्यवहार में आसानी तो हुई ही। संचार के दूसरे माध्यमों मसलन प्रिंट-रेडियो, वायरलेस- टेलीविजन -टेलीग्राफ, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिये पलक झपकते सूचनाओं का एक स्थान से दुनिया के किसी हिस्से में सूचनाओं का पहुंचाना बेहद आसान हो गया है। ऐसी भविष्यवाणी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निकोला टेस्ला ने भी की थी कि आने वाले समय में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये किसी फाइल को दुनिया के छोर से दूसरे छोर पर भेजना संभव हो जाएगा। उनकी अधिकतर भविष्यवाणियों की तरह यह भविष्यवाणी भी आज की हकीकत है। मानवी सभ्यता ने भाषा के विकास के बाद बातचीत के जरिये भी कई संस्थाओं का विकास किया है। शिक्षा भी उन संस्थानों में एक है, जहां बातचीत के जरिए ही हम अपने विचार का आदान-प्रदान करते हैं।

लोकतंत्र के बारे में युवाल नोआ हरारी का कहना है कि लोकतंत्र की संस्था भी बातचीत के जरिये ही मजबूत हुई है, और आगे बढ़ी है। आज सोशल मीडिया टेलीविजन और इंटरनेट हमारे विचारों को एक स्थान से दूसरे पर स्थान तक पहुंचाने के माध्यम है। इन माध्यमों से हम अपने विचारों से देश और दुनिया को अवगत कराते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में इन माध्यमों का उल्लेखनीय योगदान है। सवाल है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलगोरिदम ही भविष्य में हमारा भाग्य विधाता होने वाले हैं , तो हमारी बातचीत की प्रचलित परपाटी का क्या होगा?

क्या हम अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराने और उनसे असहमत होने के अपने मौलिक अधिकार से-जो किसी लोकतंत्र की खूबसूरती है, वंचित नहीं हो जाएंगे? ऐसी आशंका है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बौद्धिक आदान- प्रदान में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करेगा। हमारा दिमाग और हमारे सोच का तरीका एक कार्बनिक इन्टीटी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह की ऑर्गेनिक इन्टीटी नहीं है। यह एक ऐसी इन्टीटी है ,जो अनथक और अनवरत काम करता है।

यह न सिर्फ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि अब तो यह हमारे जिन्दगी के एक-एक पल की निगरानी भी कर रहा है। इसलिए हमारी बातचीत के दायरे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उनके व्यक्तिगत होने का भी अब दावा नहीं किया जा सकता है।

एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे विश्वास और बातचीत करने की योग्यता को भी खत्म कर रहा है। रही बात सूचनाओं की तो सूचनाएं हमेशा सत्य नहीं होती। युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि सूचनाओं की तरह सत्य भी एक बेहद पेचीदा मसला है। इस अर्थ में अगर देखा जाए तो सत्य की तह तक पहुंचाना और सत्य का ज्ञान प्राप्त करना आज के युग में कितना कठिन होता जा रहा है।अब तक हम बात-विचार को, सुनने -गुनने को, विचारों के आदान-प्रदान के जरिये एक दूसरे से सीखते -सीखाते रहे हैं। अब अगर बातचीत की भी कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, जैसा कि युवाल नोआ हरारी दावा कर रहे हैं। तब यह बेहद जरूरी है कि अभी से हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आने वाली पीढ़ी को तैयार करें।

भारत-कनाडा संबंधों का हालिया संकट
राजनीति और कूटनीति की टकराहट

भारत और कनाडा के संबंध बहुआयामी और जटिल रहे हैं, जिनमें समय-समय पर उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। दोनों देश लोकतंत्र, बहुसांस्कृतिकता और मानवाधिकारों के साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं। हालाँकि, उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी रहे हैं जो संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं, विशेषकर खालिस्तानी आंदोलन और इसके प्रभाव। हाल के वर्षों में दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों में विभिन्न बदलाव और चुनौतियाँ सामने आई हैं, जो उनके संबंधों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले एक वर्ष से जो तनाव चल रहा है, वह हाल ही में एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। इस दौरान जो घटनाएं सामने आई हैं, वे न केवल दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर चोट कर रही हैं, बल्कि एक दीर्घकालिक कूटनीतिक संकट की ओर भी इशारा कर रही हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत और कनाडा के बीच संबंधों की जड़ें औपनिवेशिक काल में हैं जब दोनों देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, कनाडा ने भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया। कनाडा ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेषकर कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में। हरित क्रांति के दौरान कनाडा ने भारत की सहायता की, जिससे भारत की कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन आरंभिक वर्षों में दोनों देशों के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

राजनीतिक संबंध

राजनीतिक दृष्टिकोण से, भारत और कनाडा के संबंध स्थिर रहे हैं, लेकिन समय-समय पर चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। विशेषकर 1980 के दशक में, खालिस्तान समर्थक आंदोलन ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनमें से अधिकांश पंजाब से हैं। इस कारण पंजाब के राजनीतिक मुद्दे, जैसे खालिस्तान आंदोलन, कनाडा की राजनीति पर भी असर डालते रहे हैं। जब भी कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को समर्थन मिलता है, तो भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया होती है।

2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने से दोनों देशों के संबंधों में और अधिक खटास आ गई। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और इसे कनाडा की घरेलू राजनीति से प्रेरित बताया। ट्रूडो की अल्पमत सरकार घरेलू राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है, और भारत का मानना है कि ट्रूडो ने सिख चरमपंथी तत्वों को खुश करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा हो गया है।

आर्थिक और व्यापारिक संबंध

आर्थिक मोर्चे पर, भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों में स्थिरता रही है। कनाडा प्राकृतिक संसाधनों का धनी देश है, जबकि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।

दोनों देशों के बीच कृषि उत्पाद, खनिज, उर्वरक, और ऊर्जा संसाधनों का व्यापार होता है। भारत के लिए कनाडा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भी है, विशेषकर यूरेनियम के मामले में। दोनों देश एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (ष्टश्वक्क) पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तनाव के कारण इस वार्ता में प्रगति धीमी रही है। यदि यह समझौता सफल होता है, तो दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, खालिस्तानी मुद्दे और ट्रूडो के आरोपों ने इन वार्ताओं को प्रभावित किया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।

सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध

भारत और कनाडा के सांस्कृतिक संबंध भी बहुत गहरे हैं। कनाडा में 1.6 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 5त्न हैं। ये प्रवासी कनाडा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और साथ ही वहाँ की सांस्कृतिक विविधता को भी समृद्ध करते हैं। भारतीय त्योहार, जैसे दिवाली और होली, कनाडा में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसके अलावा, बॉलीवुड फिल्में भी कनाडा में लोकप्रिय हैं, और कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए कनाडा के शहर एक प्रमुख स्थल बन चुके हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत और कनाडा के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। हर साल हजारों भारतीय छात्र कनाडा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को और भी मजबूत बनाता है।

सुरक्षा और रक्षा संबंध

सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बना हुआ है। आतंकवाद, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। हालांकि खालिस्तानी आंदोलन के कारण सुरक्षा सहयोग पर कुछ सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और कनाडा के बीच एक साझा समझ बनी हुई है।

राजनयिक विवाद और खालिस्तानी मुद्दा

खालिस्तानी मुद्दा भारत और कनाडा के संबंधों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियाँ और सरकार का उनके प्रति नरम रवैया भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत का मानना है कि कनाडा सिख चरमपंथियों को राजनीतिक प्रश्रय दे रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू राजनीतिक लाभ उठाना है। ट्रूडो की सरकार पर भारत लगातार दबाव डाल रही है कि वह इन चरमपंथी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन कनाडा की ओर से इस दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए हैं।

भविष्य की दिशा

इस विवाद ने भारत-कनाडा संबंधों को एक जटिल स्थिति में डाल दिया है, जहां दोनों देशों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद को फिर से स्थापित करना और इस मुद्दे का समाधान खोजना दोनों देशों के नेताओं के लिए अनिवार्य है। खालिस्तानी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति तो है, लेकिन व्यापार, प्रवास और सुरक्षा जैसे साझा हितों पर आधारित संबंधों को बनाए रखना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि कनाडा अपने आक्रामक रुख पर पुनर्विचार करता है और ट्रूडो अपनी घरेलू राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो यह दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। कुल मिलाकर, भारत और कनाडा के बीच संबंधों में मौजूद असहमति और मतभेदों के बावजूद, दोनों देशों के लिए कूटनीति और संवाद की राह पर चलना जरूरी है, ताकि दीर्घकालिक संबंधों को बनाए रखा जा सके।

(राजीव खरे स्टेट ब्यूरो चीफ़ छत्तीसगढ़)

साइबर ठगी का बढ़ता दायरा,सज्जनों पर संकट

आधुनिक संचार क्रांति के युग में मोबाइल एवं इंटरनेट जितने लाभदायक हैं उससे ज्यादा हानिकारक भी हैं। मोबाइल एवं इंटरनेट के माध्यम से भारत ही नहीं दुनिया में आए दिन साइबर ठगी की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। साइबर अपराध करने वालों की गैंग जानबूझकर ऐसे समय संबंधित को निशाना बनाती है जब वह विचार ही नहीं कर पाता और उनके द्वारा जितनी राशि की मांग की जाती है तत्काल उनके खाते में डाल देता है। इसके बाद पछतावा ही हाथ रहता है। मैं साइबर ठगी की कुछ घटनाओं का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। गुना जिले में ारका प्रसाद शर्मा महिला बाल विकास विभाग में लिपिक हैं, इनको अपरिचित मोबाइल से फोन आया और मोबाइल नंबर का केवाईसी करने की बात कही ओटीपी पूछा और बैंक खाते से 16000 रुपए निकाल लिए।

बलवीर सिंह गुर्जर निवासी साडा कॉलोनी राघौगढ़ सेवानिवृत्त गुना तहसीलदार रीडर इनके पंजाब नेशनल बैंक शाखा साडा कॉलोनी राघौगढ़ के खाते में किसी ने एक रुपया जमा किया उन्होंने जैसे ही मोबाइल खोलकर बैंक अकाउंट देखा उनके बैंक खाते से पहली बार रुपए 9970, दूसरे बार 9999 कट गए। उन्होंने तत्काल बैंक शाखा में जाकर अपना खाता ब्लॉक कराया। रुठियाई तहसील राघौगढ़ निवासी रविंद्र सिंह परिहार के पास फोन आया और बताया कि आपका बेटा पुलिस थाने में बैठा है उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो नौकरी पर है, उधर से कहा गया आपका बेटा एक लड़की के साथ होटल में अनैतिक कार्य करते हुए पकड़ा गया है। अपने बेटे को बचाना है तो तत्काल तीन लाख रुपए खाते में डालो। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा बेटे को फोन लगाओ। उन्होंने बेटे से पूछा कहां हो बेटे कहा कि मैं तो ऑफिस में हूं फिर उन्होंने जिनका फोन आया था उससे बेटे का फोन कनेक्ट कर बात करवाई। बेटे ने उनसे भलाबुरा कहा तब फोन काट दिया। एक सेवानिवृत अधिकारी जिनकी लड़की इंदौर में पढ़ती है घटना चार माह पुरानी है उनके पास फोन आया आपकी बेटी थाने में बैठी है अनैतिक स्थिति में होटल में पकड़ी है। उन्होंने दूसरे नंबर से बेटी को फोन लगाया बेटी कॉलेज में थी फोन बंद था इस कारण बात नहीं हो सकी। जिनका फोन आया था उन्होंने कहा अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तत्काल 6 लाख रुपए खाते में डालो घबराहट में उन्होंने तीन लाख रुपए खाते में भेज दिए। फिर लड़की का फोन आया कि पापा जी फोन क्यों किया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। उनके साथ साइबर ठगी हो गई। मैं स्वयं भी साइबर ठगी से होते-होते बचा। फोन पर मुझसे से कहा गया कि आपके मोबाइल नंबर की केवाईसी होना है। मैंने उनसे कहा मेरा नंबर तो एयरटेल का है अब बीएसएनएल में केवाईसी क्यों हो रही है तो उधर से जवाब आया आपकी सिम पुरानी है पहले बी एसएनएल की थी। इसलिए आपको 24 घंटे के अंदर केवाईसी करना आवश्यक है अन्यथा सिम बंद हो जाएगी । मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा कि हम आपको एक प्रोफार्मा भेज रहे हैं उसमें हम जो जानकारी पूछे उनका आप मोबाइल चालू रखकर हमें जवाब देते जाएं।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सतना ने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने हेतु प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ
सतना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सतना ने अध्यक्ष डॉ राकेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सतना जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी एवं सांसद श्री गणेश सिंह जी की उपस्थिति में डॉक्टरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपकर तुरंत निराकरण की मांग की।आई एम ए सतना के पी आर ओ डॉ अमर सिंह ने अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सतना में मेडिकल कॉलेज आ जाने के बाद शहर वासियों के लिए शीघ्र अलग से बड़े अस्पताल की आवश्यकता है जिसका निर्माण शीघ्र कराया जाए जिससे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ साथ आने वाले सभी डॉक्टर्स बेहतर सेवाएं दे सकें।इसके अलावा डॉक्टर्स की सुरक्षा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था की जाए। सतना में बाहर से आने वाले सुपरस्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए सुपरस्पेशलिटी क्लीनिक का प्रावधान किया जाए। प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन देने हेतु प्रतिनिधि मंडल में कोषाध्यक्ष डॉ ललित गुप्ता,उपाध्यक्ष डॉ सारिका कालरा, डॉ आशीष जैन , डॉ आर के नेमा, डॉ राजेश जैन,डॉ सुनील अग्रवाल, डॉ प्रवीण श्रीवास्तव , डॉ रजनीश जैसवाल,डॉ महेंद्र सिंह ,डॉ नरेंद्र शर्मा,डॉ सुनील कारखुर, डॉ राकेश जैन ,डॉ अमर सिंह, डॉ अलोक जैन,डॉ सुनीता गुप्ता , डॉ अनुज पाण्डे, डॉ रेखा पांडेय, डॉ संकल्प जैन के साथ साथ काफी संख्या मे डॉक्टर्स उपस्थित रहे।

ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध स्कूली वाहन चलाको की आकस्मिक चेकिंग

ट्रैफिक पुलिस अनूपपुर द्वारा 8 स्कूलों के 22 वाहन चालकों को किया गया चेक

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ ।
अनुपपुर, ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनूपपुर शहर मे स्थित प्राइवेट स्कूल बेथल मिशन, लिटिल स्टेप्स स्कूल, भारत ज्योति स्कूल, बचपन प्ले स्कूल, डी. व्ही .एम.स्कूल, वन स्टेप स्कूल, सी. व्ही. रमन स्कूल, सहित कुल 08 स्कूल के 22 स्कूली वाहन चालकों को ब्रइथ एनालाइजर से चेक किया गया। जिसमें कोई भी चालाक शराब के नशे में नहीं पाया गया।

बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता --पुलिस अधीक्षक
विगत दिवस यातायात पुलिस की चेकिंग में एक स्कूल वेन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोतिउर रहमान द्वारा ट्रैफिक प्रभारी को निर्देशित किया गया कि बच्चों की सुरक्षा मे लापरवाही नहीं होना चाहिए। आकस्मिक रूप से स्कूली वाहन चालकों का चेकिंग अभियान चलाया जाए। जो नशे की हालत में पाए जाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए,बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है।

वाहन चालकों को दी गई समझाइश आकस्मिक चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने के संबंध में समझाएं देते हुए बताया गया कि वाहन हमेशा निर्धारित गति में चलाएं, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, ओवरटेक करने से बचे ,यदि आवश्यक की हो तो हमेशा दाहिने तरफ से ओवरटेक करें,ब्रेकिंग डिस्टेंस का ध्यान रखें, बच्चों को वाहन से उतारते समय सावधानी रखते हुए वाहन को रोड के बाएं साइड खड़ा करें उसके बाद उन्हें उतरने दे।क्षमता से अधिक बच्चे ना बिठाये, बच्चों के अभिभावक बहुत विश्वास के साथ आपकी गाड़ी में उन्हें स्कूल भेजते हैं ।कृपया सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए उन्हें घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ें। चेकिंग में सहायक उप निरीक्षक आनंद तिवारी,प्रधान आरक्षक मनीष सिंह,रामधनी तिवारी एवं आरक्षक दिलीप सिंह उपस्थित रहे। यातायात प्रभारी ज्योति दुबे यातायात पुलिस अनूपपुरबच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है एवं इन्होंने सभी स्कूल वाहन चालक को विशेष रूप से समझाइश दी की किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाए और वाहन सावधानी पूर्वक चलाए ।

स्टेडियम उद्घाटन के आयोजन में खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किए जाने पर बिफरे लोग

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ ।
सतना, जिला फुटबॉल फेडरेशन के सचिव नलिनेन्द्र मिश्र डब्बू एवं कबड्डी, एथलीट,वॉलीबॉल सहित अन्य खेल संघ के सभी मुख्य पदाधिकारियों ने दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्धार के बाद हुए उद्घाटन अवलोकन के कार्यक्रम मे खिलाड़ियों के साथ हुए भेदभाव पर नाराजगी जताते हुए दुख व्यक्त किया है और कहा है कि जिस तरह से आज नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा खिलाड़ियों के साथ अत्यंत भेदभाव किया है वह अत्यंत पीड़ादायक है उन्होंने जिम्मेदारों पर दोषारोपण लगाते हुए कहा कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के नगरीय निकाय विकास के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गी जी के कार्यक्रम में सुबह 8:00 से खिलाड़ियों को बुला लिया गया था और व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं बनाई गई थी कार्यक्रम काफी विलंब होने की वजह से दोपहर में 1:30 बजे तक खिलाड़ी, बच्चे एवं बच्चियों को बिना नाश्ता पानी के रखा गया जिसकी वजह से वह भूख से इधर-उधर परेशान होते नजर आए और जिले के सभी नेता अपनी बडवारी करने में मस्त रहे वही कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर निगम ने नाश्ता के पैकेट बांटे परंतु बगल में खड़े खिलाड़ियों को नजर अंदाज कर दिया गया जो एक अमानवीय काम है खिलाड़ियों एवं स्टाफ तथा बच्चों बच्चियों पर हुए इस व्यवहार पर खेल संघ के सभी पदाधिकारियों सहित डब्बू मिश्र ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

जिले वासियों को नाली का पानी पिला रहा है नगर निगम का पीएचई विभाग...

सप्लाई वाले पानी में नाली के पानी की आती है बदबू..

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ ।

सतना, तो क्या नाली का पानी पिलायेगा स्मार्ट सिटी की जनता को नगर निगम...क्या यही है करोड़ों की लागत से बन रही नल जल योजना...?

नाली का पानी पीने को मजबूर सतना शहर की जनता,आखिर गंदा पानी क्यों सप्लाई कर रहे है पीएचई विभाग के जिम्मेदार,सतना जिले में नगर निगम के पीएचई द्वारा जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, वह नाली के पानी जैसा सप्लाई किया जा रहा है। आमजन से पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि लगभग महीनों से इसी प्रकार से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है।नगर निगम और पी एच आई विभाग द्वारा किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।आम जनता का कहना है की भ्रष्टाचार करते हुए जो पाइप लाइन डाली गई है ।उसके नीचे कोई बेस नहीं तैयार किया गया, और ना ही व्यवस्थित तरीके से पाइप को डाला गया है ।जिस कारण से नाली के अंदर जो पाइप डाली गई है वही से गंदा पानी बांटा जा रहा है। आज नगर निगम द्वारा इतना गंदा पानी बांटने से शहर मै बीमारी बढने की संभावना है।आज जनता के अनुसार पाइप लाइन डालने वाली कंपनी उसको देखरेख करने वाले नगर निगम इंजीनियर की भी जांच होनी चाहिए।मानक अनुरुप कार्य नही हुआ, भ्रष्टाचार करते हुए गलत तरीके से पाइप लाइन डाली गई है ।शहर की जनता आज तरह-तरह की चर्चा कर रही है की नगर निगम के इंजीनियर के साथ गांठ पर मानक अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है। उसके बाद भी उनका पेमेंट किया जाता है!सरकारी जांच करने लगे तो जनता के टैक्स के पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं हो पाएगा ।सप्लाई में भी गंदे पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी साफ और स्वच्छ पानी जनता को मिल पाएगा।वार्ड 5और 6के रहवासियों को आये दिन इसी समस्या का सामना करना पड़ता हैं,नगर निगम की आंखे बंद क्यो है।जनता की आवाज कब सुनाई देगी। साफ और स्वच्छ पानी कब से शुरू होती है ये देखने की बात है।

ट्रकों के बीच टक्कर, एक मौत, एक घायल

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ ।
सतना, जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र के कठबरिया घाटी में बढ़ा सड़क हादसा हो गया, दो ट्रकों आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, मौके पर पहुंच कर बरौंधा थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। करगिल ढ़ाबा के पास हादसा, एक गंभीर: दूसरी तरफ शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र,रीवा रोड कारगिल ढाबा के पास सड़क, किनारे ट्रक में भिड़ने से एक व्यक्ति गंभीर,रूप से घायल, घायल को इलाज के लिए,जिला अस्पताल लाया गया, जहां से हालत,गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया,सतना शहर के अंदर सड़क किनारे खड़े ट्रक और बसों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन बस और ट्रक वालों की इतनी ज्यादा है कि इन्हें किसी का डर नहीं,और न ही प्रशासन इन पर कोई कार्यवाही करता है, आखिर कब तक लोग हादसे का शिकार होते रहेंगे।

व्यापारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा

गौरव सिंघल । सिटी चीफ । देवबंद
(सहारनपुर), उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जुड़े व्यापारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। व्यापारियों ने एसडीएम देवबंद अंकुर वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में 40 लाख रुपये वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन की सीमा में रखे जाने, व्यापारियों के सैंपल न भरे जाने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में फूड एक्ट का लाइसेंस न होने पर सजा का प्रावधान खत्म करने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के लिए पूर्णकालिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने, अभिहित अधिकारी कार्यालय में शमन शुल्क जमा कराने की व्यवस्था लागू किए जाने आदि मांगें की गई। ज्ञापन देने वालों में संगठन अध्यक्ष दीपक गर्ग, श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलशाद चार्ली, अजय कुमार जैन, सुमित कुमार, अश्विनी, मोहन लाल, अमित कुमार, शाहबाज, गोपाल कुमार, नवीन गर्ग आदि मौजूद रहे।

राजस्व वसूली को लेकर पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत विभिन्न टीमों ने पांच लाख की वसूली की साथ ही बकाया अदा न करने 75 कनेक्शन काटे गए

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।
सहारनपुर । देवबंद, राजस्व वसूली को लेकर पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत विभिन्न टीमों द्वारा देवबंद नगर के अलग-अलग मोहल्लों से पांच लाख 60 हजार की वसूली की गई। साथ ही बकाया अदा न करने पर इस दौरान मौके पर ही 75 कनेक्शन काटे गए। एसडीओ अनिल कुमार चौरसिया के नेतृत्व में विद्युत टीम द्वारा देवबंद नगर के मोहल्ला नेचलगढ़, मटकोटा, पठानपुरा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाए जाने से बिजली उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा रहा। एसडीओ अनिल कुमार चौरसिया ने बताया कि सभी स्थानों पर 574 घरों को चेक किया गया। इस दौरान बिल बकाया होने के चलते 75 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। जबकि 5 लाख 60 हजार रूपए की वसूली की गई। उन्होंने बताया कि वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा।उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। बिल जमा होने पर ही उन्हें पुनः जोड़ा जाएगा। इस दौरान जेई विजय शर्मा, अरविंद कुमार, मो. जीशान, गोविंद और मुस्तकीम आदि मौजूद रहे।

नाबालिग बालिका के अपहरण तथा दुष्कर्म के प्रकरण में नागौर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही

एक आरोपी मुकेश गिरफ्तार , आरोपी को कस्बा मेड़तारोड़ से किया दस्तयाब

एजाज़ अहमद उस्मानी । सिटी चीफ ।
(राजस्थान) मेड़ता रोड, नाबालिक बालिका के अपहरण तथा दुष्कर्म के मामले को लेकर मेड़ता रोड पुलिस ने एक नाम जज आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया है। मेड़ता रोड थाना अधिकारी राधाकिशन मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 सितंबर 24 को बालिका के पिता ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरी पुत्री जो 23 जनवरी 24 को रात्रि 8 बजे बिना बताये कहीं चली गई हैं तथा 18 सितंबर 24 को शाम 6 बजे वापिस आई और बताया कि मुकेश मुझे जबरदस्ती डरा-धमका कर अपहरण कर ले गया व मेरे साथ दुष्कर्म किया। जिस पर मेड़ता रोड पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को मेड़ता रोड से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना मेड़ता रोड से मिली जानकारी के अनुसार राधाकिशन मीणा उ.नि. थानाधिकारी मय टीम द्वारा मुखीबर की सूचना पर मुकेश पुत्र पप्पुराम जाति वाल्मिकी उम्र 30 साल निवासी हरिजनों का बास, रियांबडी थाना पादूकलां जिला नागौर को जुर्म धारा 366,376 (2) (छ) 384 भादसं में गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

जिलाधिकारी ने किया जिला विद्यालय कार्यालय का निरीक्षण

जनपदवासियों के लिए बेहतर पुस्तकालय तैयार करने के लिए योजना बनाने के दिए निर्देश

गौरव सिंघल | सिटी चीफ | सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा जिला विद्यालय कार्यालय का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कार्यालय में जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिए। इसी के साथ उन्होंने एक्सईन लोनिवि को प्रस्तावित डिजिटल लाईब्रेरी के लिए यथाशीघ्र डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाईब्रेरी परम्परागत एवं डिजिटल दोनों रूपों में संचालित की जाएगी। इसमें कम्प्यूटर के साथ-साथ पुस्तक रैक की सुविधा भी होगी जिससे पुस्तकें प्राप्त एवं जमा कराई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि जनपदवासियों के लिए बेहतर पुस्तकालय तैयार करने के लिए योजना बनाई जाए ताकि पढने वाले छात्रों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक हर्ष देव स्वामी, एक्सईन लोक निर्माण विभाग धमेन्द्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज

आरोपी युवक की ओर से भी कराया मुकदमा दर्ज, जांच एसएचओ मेड़ता को सौंपी

एजाज़ अहमद उस्मानी । सिटी चीफ ।

(राजस्थान) मेड़ता रोड, मेड़ता रोड कस्बे की एक महिला के साथ कस्बे के ही एक युवक के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया। मेड़ता रोड थाना अधिकारी राधाकिशन मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि

मेड़ता रोड कस्बे की रहने वाली महिला के पति ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह तथा उसका लड़का दुकान पर गए हुए थे इस दौरान आरोपी युवक पीछे से उसके घर में घुसा तथा उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। महिला के पति ने रिपोर्ट में बताया कि इससे पहले भी आरोपी युवक दो बार ऐसी हरकतें कर चुका है लेकिन शर्म और लाल लज्जा के भय से किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया था। लेकिन आरोपी ने जब तीसरी बात ऐसी हरकत की तो पुलिस का सहारा लेना पड़ा। महिला के पति ने मेड़ता रोड थाना अधिकारी को बताया कि युवक के घर में घुसने को पर उसकी पत्नी चिल्लाई तथा आसपास के महिलाओं को बुलाया महिलाओं ने बीच बाजार करके उसकी पत्नी को आरोपी युवक के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया उसके बावजूद युवक नहीं माना। घटना को लेकर स्थानीय पुलिस थाना मेड़ता रोड में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी युवक द्वारा भी महिला के पति तथा अन्य लोगों पर युवक के साथ डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। युवक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक रेलवे के लोको में कचरा फेंकने गया था जिस पर महिला के पति तथा अन्य लोगों ने पीछे से डंडों से वार कर दिया। जिससे युवक के सर में गहरी चोटें आई हैं। मेड़ता रोड पुलिस ने दोनों परिवारों की ओर से मुकदमा दर्ज कर मामला एससी-एसटी का होने पर जांच एस एच ओ मेड़ता को सौंप दी है।

ऑनलाईन आवेदनों के लिए शासन से नियुक्त अधिकारियों द्वारा जन सूचना एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

नियमावली में निहित प्राविधानों का किया जाए शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।

सहारनपुर, अपर आयुक्त प्रशासन सुरेन्द्र राम की अध्यक्षता एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के डॉ. राहुल सिंह, स्टेट रिसोर्स पर्सन, आरटीआई, राजा राम, सेवा निवृत्त, आई0ए0एस0, स्टेट रिसोर्स पर्सन (आरटीआई) वी. के. गंगवार, मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011, उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के मुख्य प्राविधानों के संबंध में सहारनपुर मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आवेदनों एवं प्रथम अपीलों को ऑनलाईन प्राप्त किए जाने हेतु वेब पोर्टल के समुचित क्रियान्वयन के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए गये कि सूचना के निस्तारण में अधिनियम की धारा व उ0प्र0 सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली में निहित प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

स्टेट टीम हैड आरटीआई ऑनलाइन डॉ. राहुल सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राज्य में आईटीआई ऑनलाइन व्यवस्था लागू है जिसका लाभ जनता द्वारा लिया जा सकता है। पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बढाने के लिए ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाइन व्यवस्था भी लागू की गयी है। जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत जनता को सेवा का अधिकार भी प्राप्त हो गया है जिसके अन्तर्गत 421 सेवाएं अन्तर्निहित है। इन सेवाओं को शासन की मंशा के अनुसार निश्चित समयबद्धता के साथ क्रियान्वित किया जाना है। वी.के. गंगवार ने जनहित गारण्टी अधिनियम के बारे में बताया कि सेवा देर में देने अथवा जानबूझकर की स्थिति में सेवा देने हेतु पदाभिहित अधिकारी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी संस्तुति की जा सकती है। जनहित गारण्टी अधिनियम के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) उ0प्र0 प्रयागराज के मुख्य निरीक्षक एवं उप मुख्य निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। सहारनपुर मण्डल के लिए श्री कुलदीप भारद्वाज निरीक्षक राजकीय कार्यालय (मण्डलीय अधिकारी) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुलदीप भारद्वाज, निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर सहित तीनों जनपदों के मंडलीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारीगण, तहसीलदार उपस्थित रहे।

कमिश्नर की पहल पर ग्राम लहसुना में आयोजित हुआ संभाग स्तरीय जन कल्याण शिविर

कमिश्नर एवं जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में सुनी गई लोगों की समस्याएं

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ ।

अनूपपुर, कमिश्नर शहडोल संभाग श्री श्रीमन शुक्ला की पहल पर शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी के दूरस्थ जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायत लहसुना में संभाग स्तरीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कमिश्नर शहडोल संभाग श्रीमन शुक्ला, अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल रौतेल, विधायक पुष्पराजगढ़ श्री फुंदेलाल मार्को, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती वाल्मीकि राठौर, कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा सहित अन्य अधिकारी की उपस्थिति में जनमानस की समस्याएं सुनी गई एवं समस्याओं के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। संभाग स्तरीय जन कल्याण शिविर में लगभग 352 समस्या मूलक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिसंख्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष आवेदनों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुए कमिश्नर शहडोल संभाग ने समय सीमा में आवेदनों की निराकरण करने की निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जनकल्याण शिविर में विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जनकल्याण शिविर में कृषि विभाग ,उद्यानिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, ग्रामीण एवं यांत्रिकी सेवा विभाग, पशुपालन विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, जनजातीय कार्य विभाग शिक्षा विभाग सहित अन्य विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाए गए थे। जिनके माध्यम से ग्रामीणों को शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई ।संभाग स्तरीय जनकल्याण शिविर में स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर का मौके पर आयोजन किया गया जहां लगभग 330 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें नि:शुल्क दवाइयां वितरित की गई। जनकल्याण शिविर में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 89 हितग्राहियों को डिवर्मिंग, लिवर टॉनिक, दस्त गोली एवं पशुओं को होने वाले घाव के उपचार के लिए मलहम का वितरण किया गया। इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा 14 हितग्राहियों को मसूर बीज के मिनी किड्स का नि:शुल्क वितरण किया गया तथा 13 हितग्राहियों को स्वाइल हेल्थ कार्ड का वितरण भी किया गया। शिविर लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हितग्राही नित्या सैनी, प्रीति मैना एवं स्नेह सिंह को प्रतीक स्वरूप स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया ।जनकल्याण शिविर संयुक्त आयुक्त विकास श्री मगन सिंह कनेश, संयुक्त संचालक शिक्षा श्री सुखदेव सिंह मरावी, संयुक्त संचालक कृषि श्री जे.एस. पेंड्राम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी श्रीमती अंजलि द्विवेदी सहित अनूपपुर जिले के सभी विभागों के विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

जोधपुर मंडल के जैसलमेर-जोधपुर रेल खंड के मारवाड़ मथानिया स्टेशन की लूप लाईन को नई सिग्नल प्रणाली से किया आधुनिक और नवीनतम

एजाज़ अहमद उस्मानी । सिटी चीफ । (राजस्थान) मेड़ता रोड, जैसलमेर-जोधपुर रोड रेलखंड के जोधपुर मंडल के मारवाड़ मथानिया स्टेशन के अतिरिक्त लूप लाईन को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से बदलने के साथ ही इस खंड पर आधुनिक सिंगनलिंग प्रणाली स्थापित कर दी गई है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे श्री अमिताभ के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में मारवाड़ मथानिया (लूप लाईन) स्टेशन को नई सिग्नल प्रणाली का कुशलतापूर्वक कलर लाइट सिगनल प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और आधुनिक सिग्नल प्रणाली से बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कलर लाइट सिग्नल वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से ट्रेनों के सुरक्षित और कुशल संचालन में मदद मिलेगी। इस प्रणाली के साथ स्टेशन पर दोनों दिशाओं से ट्रेनों को एक साथ आने और भेजे जाने की सुविधा के चालू होने से स्टेशन पर ट्रेन क्रॉसिंग समय में सुधार होगा एवं ट्रेनों के समय पालन मे भी बढ़ोतरी होगी, इसके अलावा नई एवं आधुनिक ब्लॉक प्रणाली के लागू हो जाने से अब लोको पायलेटों को अवांछित तनाव से भी छुटकारा मिलेगा, इससे संरक्षा में भी बढावा मिलेगा तथा ट्रेनों के सुरक्षित और कुशल संचालन में सहायता मिलेगी। इस दौरान सीएओ/सी/एनडब्ल्यूआर मुरारी लाल मीणा, सीपीएम/गतिशक्ति जोधपुर अशोक कुमार धाकड़, वरिष्ठ मंडल सिग्नल/ दूरसंचार इंजीनियर अनुपम कुमार, उप मुख्य सिग्नल दूरसंचार इंजीनियर दीपक चौधरी, डिप्टी जीएसयू

प्रवेंद्र सिंह, सहायक परिचालन प्रबंधक बी एस वर्मा सहित मंडल के अधिकारीकरण मौजूद थे।

क्या होती हैं लूप लाईन सिनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि रेलवे में ट्रेनों के संचालन के लिए अलग-अलग लाइनें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें लूप लाइन का भी अधिक महत्व है। इस लाइन को किसी रेलवे स्टेशन के पास बनाया जाता है, जिससे वहां से गुजरने वाली ट्रेन को हॉल्ट मिल सके। इस लाइन का इस्तेमाल ट्रेन को खड़ा करने के लिए किया जाता है।

तीर्थ दर्शन में खाचरोद जनपद के साथ सौतेला व्यवहार क्यो

उज्जैन

5 यात्रा में किसी भी नही पहुचा चयन का आंकड़ा दहाई तक

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में हाल ही में सितंबर और अक्टूबर माह में पांच यात्राएं निकली जिन यात्राओं में चयनित यात्रियों की सूची यदि देखें तो उसमें देखने में आता है कि जिले की सबसे बड़ी जनपद पंचायत खाचरोद के साथ हर बार सौतेला व्यवहार ही होता हुआ दिख रहा है क्योंकि तीर्थ दर्शन यात्रा में चयनित यात्रियों की सूची देखे तो चुनिंदा यात्रा को छोड़ दे तो जिले की सबसे बड़ी जनपद कही जाने वाली जनपद से किसी यात्रा में 1 तो किसी किसी यात्रा में 2 या 3 यात्रियों का चयन हुआ ! हाल ही में सितंबर ओर अक्टूबर में तीर्थ दर्शन योजना के अंतगर्त रामेश्वर के लिए 21 सितम्बर को रवाना हुई यात्रा में नाम मात्र के चयन हुए उसके बाद, मथुरा वृंदावन यात्रा में जनपद से केवल 1 यात्री का चयन हुआ और जब यह मुद्दा मीडिया में सुर्खियां बना और क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य श्रीमतिराधिका कुंवर गजेन्द्रसिंह ने इस पर संज्ञान लिया तो उनके हस्तक्षेप ले बाद 6 यात्रीयो का ओर चयन हो पाया, फीर कामाख्या देवी यात्रा जो 13 अक्टूबर को गई उसमें जनपद से 3 यात्रीयो का चयन हुआ, वही अब 21 अक्टूबर को अमृतसर ले लिए यात्रा जाने वाली है जिसमे खाचरौद जनपद पंचायत से 2 यात्रीयो का चयन हुआ है ! इसके लिहाज से यह कहना गलत नही होगा कि जिले की सबसे बड़ी जनपद पँचायत के साथ तीर्थ दर्शन योजना में सौतेला व्यवहार ही होता है !

निकायों के लिए अलग अलग हो लाट्री -अभी तक तीर्थ दर्शन यात्रा में चयन के लिए पूरे जिले की एक साथ लॉटरी निकल जाती है जिसके कारण देखने में आता है कि किसी जनपद या नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम से अधिक यात्रियों का चयन होता है तो किसी निकाय से नाम मात्र यात्रियों का चयन होता है इसके लिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वह लक्ष्य के अनुसार सभी निकायों के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय करें और उसके बाद सभी निकायों से आने वाले आवेदनों की अलग-अलग लॉटरी व्यवस्था की जाए यदि ऐसा होता है तो सभी निकायों को एक निश्चित अनुपात में तीर्थ दर्शन यात्रियों का लाभ वहां के निवास करने वाले यात्रियों को मिल सकता है किंतु क्या जनप्रतिनिधि ऐसा करवा पाएंगे यह भी एक बड़ा प्रश्न है !

स्थाई सीईओ ही नहीं भटकते हैं लोग - खाचरोद जनपद पंचायत की बात करें तो यहां वर्तमान में सीईओ जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पोस्ट पर कोई भी स्थाई अधिकारी नहीं है और वर्तमान में इस पोस्ट पर अन्य जनपद पंचायत के अधिकारियों के पास चार्ज है ऐसे में सप्ताह में एक या दो दिन इन अधिकारियों का आना होता है जिले की सबसे बड़ी जनपद होने के बाद यह हाल है जिसके कारण जनपद के कई सारे कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं और लोग भी इधर-उधर भटकते रहते हैं जबकि आए दिन जनपद पंचायत कार्यालय की मुख्य कार्यपालन अधिकारी का गेट अधिकांश समय बंद ही मिलता है क्या यहां की जनप्रतिनिधि एक स्थाई सीईओ की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे क्योंकि यह पोस्ट काफी दिनों से रिक्त ही है जहा पोस्टिंग तो हुई थी पर जॉइनिंग अब तक नहीं हुई !

साधारण सभा मे रखेंगे विषय - पूर्व में भी मेरे द्वारा इस विषय में बात की गई थी और अब भी साधारण सभा के साथ ही अन्य स्थानों पर इस बात को रखते हुए किस प्रकार से क्षेत्र को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए प्रयास करूंगी !

अन्नपूर्णा पुलिस की बड़ी कार्यवाही आटो रिक्सा मे छूटा जेवरात से भरा बैग ढूढने मे मिली सफलता

करीब 12 लाख रूपये का सोने चांदी के जेवरात ढूढ निकाले ।

थाना अन्नपूर्णा पर फरियादी शिवानी पिता भैरू सिंह बघेल उम्र 24 साल निवासी 56 मिश्रनगर इंदौर ने थाने पर उपस्थित होकर बताया कि मे अपने गांव अलीराजपुर से बस से इंदौर आई इंदौर मे चोईथराम चौराहे पर उतर कर वहां से आटो मे बैठ कर अपने घर मिश्रनगर अन्नपूर्णा जा रही थी चाणक्यपुरी चौराहे पर उतर गई मेरे पास तीन बैग थे जिसमे से दो उतार लिये तथा एक बैग नही उतारा मुझे घर जा कर याद आया कि मेरा एक बैग आटो रिक्सा मे छूट गया है । बैग मे करीब 120 ग्राम सोना एवं 3 किलो ग्राम चांदी एवं नगदी रूपये थे । रात्री अधिक होने से दूसरे दिन थाने पर आवेदन दिया । फरियादी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुये पुलिस उपायुक्त इंदौर जोन 4 ऋषिकेश मीना एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आनंद यादव के निर्देशन मे तथा एसीपी अन्नपूर्णा नंदनी शर्मा के नेतृत्व मे थाना प्रभारी अन्नपूर्णा सुनील सेजवार द्वारा त्वरित टीम गठित कर आटो रिक्सा की तलाश हेतु लगाया । पुलिस टीम द्वारा चोईथराम चौराहे से द्वारिकापुरी तक के करीब 200 सी सी टी व्ही कैमरे देखने के बाद आटो रिक्सा का पता लगाया , आटो रिक्सा चालक की पहचान चुन्नीलाल पिता भैराजी साल्वे निवासी 486 द्वारिकापुरी के रूप मे हुई । पुलिस टीम आटो रिक्सा चालक के घर पहुची जिससे बैग के संबंध मे पूछताछ करते आटो चालक चुन्नीलाल द्वारा बताया कि मैने घर पर आकर देखा तो मेरी आटो रिक्सा मे किसी सवारी का बैग छूट गया रात्रि अधिक होने से मेने बैग आटो मे निकाल कर घर मे सम्भालकर रख दिया था उसके बाद मैने बैग मालिक को ढूढने का प्रयास करता रहा कि जिससे बैग मालिक तक पहुच जाये । उससे पहले पुलिस मेरे आटो रिक्सा व मुझे ढूढते हुये मेरे घर तक आ गई । आटो रिक्सा चालक द्वारा बैग पुलिस टीम को निकल कर दिया जिसमे फरियादी द्वारा बताया पूरा समान यथावत मिला । बैग मे करीब 12 लाख रूपये के सोने चांदी के जेवरात व नगदी रूपये थे । आटो रिक्सा चालक द्वारा ईमानदारी पूर्वक फरियादी का सामान यथावत घर मे सुरक्षित रखा था । फरियादी को उसका समस्त समान मिलने पर फरियादी व परिवार के द्वारा खुशी जाहिर कर अन्नपूर्णा पुलिस को धन्यवाद दिया तथा पुलिस के प्रति विश्वास रखने का संदेश दिया । उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सुनील सेजवार , आर. ऋषिकेश रावत , आर. जितेन्द्र सोलंकी , आर. राकेश , आर. विश्वेन्द् की सहरानीय भूमिका रही ।

शेख़ ताहेर भाई मर्चेंट को गुरुजी ने नवाजा!

नानपुर दाऊदी बोहरा समाज के अगाध श्रद्धाकेंद्र धर्मगुरु डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने आज गुजरात के दुम्मस (सुरत) में नानपुर बोहरा समाज के वरिष्ठ समाजसेवी ताहेरी भाई मर्चेंट (बावा) को शेख़ (हदियत शरफ़) की उपाधि से अलंकृत कर शेख़ की पगड़ी पहनाई! शेख़ ताहेरीभाई मर्चेंट (सैफ) को हदीयत मिलने पर परिजनो एवम् समाज के लोगों में हर्ष व्याप्त है! समाज के वयोवृद्ध शेख़ अकबरभाई, शेख हुसैनीभाई, ज्येष्ठ भ्राता शेख़ शब्बीरभाई मर्चेंट वाली मु. खुजैमाभाई राज, मुल्ला कैजारभाई दाऊदी, मु. हुसैनीभाई राज, शाकिरभाई जाना, फखरीभाई, मुल्ला इक़बालभाई, मोहम्मदीभाई मर्चेंट, खुजैमाभाई मर्चेंट, वरिष्ठ पत्रकार मुल्ला शफ़क़त दाऊदी, शब्बीरभाई खेड़ी, हुजैफा मर्चेंट, युसुफ लाला, शब्बरभाई बांसवाड़ा, समाजसेवी डॉ. रामेश्वरजी गुप्ता, पत्रकार प्रदीप क्षीरसागर, मनीष(गजा) माली, जितेंद्र राज वाणी, जितेंद्र प्रसाद वाणी, हाजी सिराजुद्दीन पठान, अब्दुल अजीज शेख (चांद मामा) सहित अनेकों ग्रामीणों ने धर्मगुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शेख़ ताहेरभाई को मुबारकबाद पेश की!!

पेसा एक्ट के तहत नवीन ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित

बाग

जिले की जनपद पंचायत बाग ग्राम पंचायत झिरपन्या मजरा मालपुरा में पेसा ग्राम सभा का आयोजन कर नवीन ग्रामसभा के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।

बैठक में पेसा ब्लॉक समन्वयक कैलाश डोडवे एवं मोबेलाईजर कैलाश अनारे ने मध्यप्रदेश पंचायत अनुबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) नियम 2022 पेसा एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक समझया गया पेसा से संबंधित जल,जंगल,जमीन,श्रमिक शक्ति योजना, मादक पदार्थ पर नियंत्रण,लघु वनोपज,गांव में शान्ति बनाए रखने के लिए शान्ति एवं विवाद निवारण समिति काम करेंगी,वन संसाधन समिति, ग्राम सभा निधि, मातृ सहयोगिनी समिति एवं विभिन्न समिति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई सदियों से चली आ रही रूढ़ी प्रथा संस्कृति परंपरा के बारे में बताया गया पेसा कानून लागू से ग्रामीणों को विशेष अधिकार मिला है तथा ग्राम सभा के बारे में बताया जिसमे ग्राम सभा का गठन,ग्राम सभा की शक्तियां , प्रबंधन,खनिज,मादक पदार्थों पर पाबंदी, श्रम शक्ति की योजना,गांव में वनोपज ,महिला बाल विकास योजना एवं आदिवासी परंपरा को बनाए रखने की जानकारी दी गई ।

ग्रामिण जनों ने सर्वसम्मति से ग्राम सभा अध्यक्ष का चयन किया गया। बैठक में पेसा मोबेलाइजर एवं मालपुरा के मतदाता महिला, पुरुष, बुजुर्ग,बड़ी संख्या में उपस्थित रहे एवं उनके द्वारा मालपुरा का नजरी नक्शा बनाकर प्रस्ताव तैयार किया गया।

हिंदू समाज को संगठित होना आवश्यक डां पाटीदार शताब्दी वर्ष में निकला पथ

बाग

बाग– नगर मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रमुख मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। जगह-जगह नगरवासियों ने गणवेश धारी स्वयंसेवकों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।संघ ने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है। हमारी संस्कृति और समाज को बचाने के लिए हिंदू समाज को संगठित होना आवश्यक है। जाती व्यवस्था हमारी संस्कृति में नही थी, लेकिन कुछ लोगो ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिय हिंदू समाज को जातियों में बाट दिया। उसी का दुष्परिणाम है की आज हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसे रोकने के लिए हिंदुओं को एकजुट होकर काम करना होगा। उक्त बात संघ के जिला संपर्क के प्रमुख डां प्रवीण जी पाटीदार ने बुधवार को विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा निकले पथ संचलन के पूर्व सांई सिटी कालोनी स्थित माधव शाखा संघ स्थान पर मंचासीन अतिथि बाग खंड संघचालक मनोज मुकाती की गरीमा उपस्थित मे करते हुए पर्यावरण, स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता एवं नागरिक संहिता पर उपस्थिति स्वयंसेवक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा की 27 सितंबर 1925 को डा केशव बलिराम हेडगावकार जी ने राष्ट्रीय दिशमी स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। प्रतिवर्ष विजयादशमी पर पूरे देश भर में संघ का पथ संचलन निकला है इसी कडी मे बाग मे भी प्रभावी पथ संचलन निकाला गया ।

एच आई व्ही एवं समाज में फेली इसके प्रति भ्रांतियों दूर करने के लिए

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरुक किया

बाग बाग – विकासखण्ड बाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशानुसार बुधवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिसमें नाटक प्रस्तुति गंगा प्रसाद डामर दल प्रमुख आदिवासी नुक्कड़ नाटक दल भामल झाबुआ म.प्र. द्वारा एच आई व्ही व एड्स प्रति जागरूकता फैलाने और समाज में इसके प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से विजय इस्तम्भ बाजार में एक विशेष नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया ।नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य एच आई व्ही व एड्स की रोकथामए बचाव और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नाटक के माध्यम से यह बताया कि किस प्रकार एच आई व्ही संक्रमण से बचा जा सकता है। संक्रमित व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और कैसे जागरूकता ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। इस दोरान स्वास्थ्य विभाग के डॉ.राजेंद्र कुमार वर्मा चीफ मेडिकल आफिसर , , डॉ.सुरेखा परिहार ,बी.सी.एम. बी ई ई लोकेन्द्र भदौरिया का विशेष सहयोग रहा ।बाग विक्सखंड की समस्त आशा कार्यकर्ता,ओर आशा सुपरवाइजर एवं स्वयंसेवकों द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया।

कृषि उपज मंडी लोहारदा मे बैठक सम्पन्न

काटाफोड़ –कलेक्टर देवास एवं संयुक्त संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय उज्जैन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में खरीफ विपणन कार्य योजना वर्ष 2024-25 के सुचारू संचालन हेतु भारसाधक अधिकारी महोदय हरिओम ठाकुर की अध्यक्षता में एवं मण्डी सचिव आर0 के0 साकेत एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया जिसमे मण्डी नियमन ईमण्डी मध्यप्रदेश योजना फार्मगेट के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रवेश, निलाम, तौल भुगतान, निकासी प्रांगण व्यवस्था एवं कृषि उपज से संबंधित शिकायतों के निराकरण संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें भारसाधक अधिकारी महोदय द्वारा कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु विशेष निर्देश दिये गये। उक्त बैठक से पूर्व मण्डी प्रांगण लोहारदा एवं उपमण्डी प्रांगण सतवास में मध्यप्रदेश फार्मगेट एप के प्रचार प्रसार हेतु पंजीकरण केंम्प लगाकर 31 कृषकों का पंजीकरण किया गया। उक्त बैठक में लोहारदा मण्डी के व्यापारी संघ से शैलेष होलानी, नटवर बियाणी, श्री राजू गोयल, राजेश होलानी,दीपक पाटोदी, गोविन्द साहू, एवं पिन्टू राठौर, आदि उपस्थित रहे एवं इनके द्वारा मण्डी संचालन से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किये गये। बैठक का समापन मण्डी सचिव श्री साकेत के धन्यवाद प्रस्ताव से हुआ

समरथ ने बैंक की नौकरी छोड़ 27 लाख में गार्लिक प्रोसेसिंग का उद्योग स्थापित किया

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना ने समरथ की जिंदगी बदल दी

मंदसौर / मंदसौर जिले के गांव गुर्जर बर्डीया के रहने वाले समरथ गुर्जर (9826929713) एक समय बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें नौकरी करना ठीक नहीं लगा। उनका सपना था कि, मैं 1 दिन अन्य लोगों को भी रोजगार दूंगा। उनके इस सपने को पूरा करने में उद्यानिकी विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना ने पूरा सहयोग किया। समरथ को उद्यानिकी विभाग के माध्यम से जानकारी मिली की वह गार्लिक के लिए उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए सरकार ने योजना चलाई है। उन्होंने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया और उन्हें बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 27 लाख 90 हजार का लोन मिला। जिस पर उन्हें 10 लाख रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की गई। श्री समरथ गुर्जर कहते हैं, कि मैंने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया और मात्र 5 महीने में मुझे लोन प्राप्त हो गया। मेने 2 माह पहले ही यूनिट स्थापित की है। इसके माध्यम से गार्लिक बना रहा हूं और उस गार्लिक को मंदसौर के साथ-साथ अन्य जिलों में भेजता हू। इस मशीन से लहसुन की ग्रेडिंग भी होती है। जिससे मंडी में लहसुन की दाम अधिक मिलते हैं। आसपास के अन्य किसान भी लहसुन की ग्रेडिंग कराने के लिए आते हैं। उससे भी मुझे अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही हैं। इनका कहना है कि मेरा उद्योग इसी तरह से चलता रहा तो मैं आगामी 1 से 2 वर्ष में लोन का सारा पैसा भी जमा करा दूंगा।मेरी यूनिट को देखने के लिए अन्य जिलों से भी किसान आते हैं। भविष्य में इसको और बड़ा करने की सोच रहे हैं। इसके माध्यम से लहसुन के अन्य प्रोडक्ट का भी उत्पादन करेंगे। इसके साथ ही गार्लिक को रखने के लिए एक कोल्ड रूम भी बनाएंगे। इस यूनिट को स्थापित करने में कलेक्टर श्री गौतम सिंह एवं उद्यानिकी विभाग का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। मैं अब पूरे परिवार को रोजगार दे रहा हूं। इसके साथ ही 5 से 6 अन्य युवाओं को भी रोजगार दिया है। यह यूनिट इतनी अच्छी है, कि मेरे बच्चे भी इसमें पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये स्वयं तो आगे बढ़े है साथ में अन्य किसानों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इनका विशेष तौर पर कहना है, कि मेरी स्वयं की गार्लिक यूनिट स्थापित होने की वजह से परिवार, गांव, समाज एवं रिश्तेदारी में मेरा मान सम्मान बढ़ा है।

राज्य स्तरीय नारी सम्मान एवं समाज सेवा पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित

मन्दसौर महिला, बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता एवं साहसिक कार्यों के लिये व्यक्तिगत/संस्थागत श्रेणी में 6 राज्य एवं जिला स्तरीय पुरस्कार दिये जाते हैं। वर्ष 2024 के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट https://mpwcdmis.gov.in/ पर उपलब्ध है। आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि के पहले जमा किया जा सकता है।

रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार

महिला और बच्चों को उत्पीड़न से बचाने, उनके पुनर्वास में योगदान, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरितियों को रोकने का साहसिक कार्य करने वाली मध्यप्रदेश की महिला/बालिका को रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये की राशि प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर 2024 निर्धारित है। इन पुरस्कारों के नाम की घोषणा फरवरी माह में की जाएगी, 8 मार्च महिला दिवस पर इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार

महिलाओं से संबंधित समाज सुधार (स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, अधिकारों के प्रति जागृति, सामाजिक उत्थान) के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं प्रमाणित कार्य करने वाली मध्यप्रदेश की महिलाओं को राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये की राशि, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार

महिलाओं से संबंधित समाज सुधार (स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, अधिकारों के प्रति जागृति, सामाजिक उत्थान) के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं प्रमाणित कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति/संस्था को विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये की राशि, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार

ऐसी घटना जिसमें किसी महिला द्वारा आपराधिक या असामाजिक तत्वों के विरूद्ध साहस का प्रदर्शन कर स्वयं का अथवा अन्य किसी महिला की सुरक्षा एवं बचाव के लिये अवर्णनीय साहसिक कार्य किया हो, को मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आवेदक द्वारा यह साहसिक कार्य एक जनवरी से 31 दिसम्बर 2024 के बीच किया गया हो। राज्य स्तर पर चयनित किन्ही 2 महिला व 2 पुरूषों को एक लाख रूपये से सम्मानित किया जायेगा। जिला स्तर पर 50 हजार रूपये की राशि, प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है।

अरूणा शानबाग साहस पुरस्कार

यह पुरूस्कार उस घटना के लिये जिसमें किसी महिला द्वारा किसी भी हिंसा में स्वयं या किसी अन्य के बचाव के लिये वीरतापूर्वक कार्य किया गया हो, को अरूणा शानबाग साहस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आवेदक द्वारा यह कार्यएक जनवरी से 31 दिसम्बर 2024 के बीच किया गया हो। यह पुरस्कार राज्य स्तर पर चयनित किसी एक महिला को दिया जायेगा, जिसमें एक लाख रूपये की राशि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार

आपराधिक और असामाजिक तत्वों के विरूद्ध साहस का प्रदर्शन करते हुए स्वयं या किसी अन्य महिला का बचाव करने वाली महिला अथवा महिलाओं का बचाव करने वाले पुरूषों को भी सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार में एक लाख रूपये की राशि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

सरदार वल्लभभाई पटेल स्कूल में निःशुल्क साइकिल वितरण की गई

मन्दसौर सरदार वल्लभभाई पटेल क्रमांक 2 स्कूल में मध्यप्रदेश शासन द्वारा बालकों को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, पार्षद, प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थिति थे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गुर्जर के द्वारा कहा गया कि सरकार के द्वारा सभी विद्यार्थियों को हर संभव मदद दी जा रही है । सरकार द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चला रखी है जिससे सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं लाभ मिल रहा है । सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए हैं जिससे आज विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल रहा है ।

चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों को दो बैच में विभाजित कर ओपीडी तथा आईपीडी का दौरा करवाया

मंदसौर/ मेडिकल कॉलेज डीन श्रीमती शशि गांधी द्वारा बताया गया कि, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित एमबीबीएस छात्रों को दो बैच में विभाजित कर अस्पताल के विभिन्न विभागों जिसमें ओपीडी तथा आईपीडी का दौरा करवाया गया। जिसमें छात्रों को विभिन्न विभागों की विस्तृत रूप से जानकारी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षकों द्वारा दी गई। जिसमें डॉ लवी उकावत, नाक कान गला रोग विभाग, डॉ रणसिंह तंवर, चर्म रोग विभाग, डॉ निशांत पटेल, मनोरोग विभाग, डॉ इशांत कुमार चौरसिया सर्जरी विभाग, डॉ अजय पाटीदार सर्जरी विभाग, डॉ गौरव अखंड अस्थि रोग विभाग, डॉ दीपक मकवाना मेडिसिन विभाग, डॉ नेकी मिनारे, बाल्य एवं शिशु रोग विभाग, डॉ करूणा मेरावी स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने छात्रों को विस्तार से जानकारी प्रदान की।

तनाव के बीच उज्जल दोसांझ का बड़ा बयान

कहा- टूडो खालिस्तानियों पर कार्रवाई करने में विफल

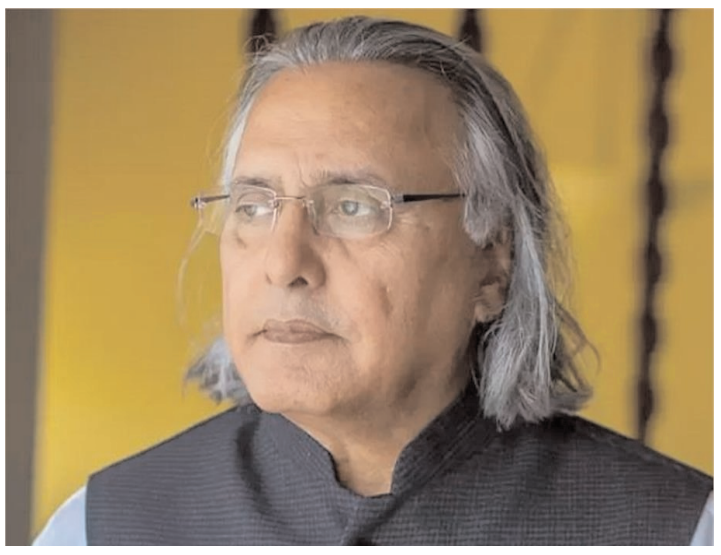

इंटरनेशनल डेस्क: कनाडा और भारत के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निझर की हत्या पर भारत और कनाडा ने कई वरिष्ठ राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया. इस सब के दौरान कनाडा ने भारत पर कई आरोप भी लगाए हैं। इन सबके बीच कनाडा के एक न्यूज चैनल सीबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ब्रिटिश कोलंबिया के भारतीय मूल के पूर्व प्रधानमंत्री उज्जल देव दोसांझ ने कनाडा और भारत के बीच ताजा घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कनाडा की लिबरल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत और कनाडा द्वारा किए जा रहे जैसे को तैसा का आम कनाडाई लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। कनाडा और भारत के संबंधों का एक लंबा इतिहास है लेकिन वर्तमान में यह अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। कनाडा सरकार खालिस्तान से जुड़े मुद्दों पर काबू पाने में नाकाम रही है।

इस बीच दोसांझ ने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसे हालात भारत के परमाणु परीक्षण के दौरान भी नहीं बने थे। कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा जिस तरह से माहौल खराब किया जा रहा है, उससे कनाडा के लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया हादसे के दौरान, न पहले और न ही अब हालात बदले हैं।

खालिस्तानी खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब से कनाडा के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है और पद संभाला है, तब से वह खालिस्तानियों से घिरे हुए हैं। ये लोग उनके सर्कल में हैं, उनकी कैबिनेट में हैं और जगमीत सिंह की पार्टी से भी इनका गठबंधन है। जो खुद खालिस्तानी हैं। हालांकि, उन्होंने कभी हिंसा नहीं भड़काई। खालिस्तानी लंबे समय से समुदाय के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, जिसमें एयर इंडिया की घटना भी शामिल है।

अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। कनाडा विफल हो गया है. हम यह सलाह नहीं दे रहे हैं कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए बल्कि यह कह रहे हैं कि कनाडा के लोग भी इससे पीड़ित हैं।

इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार तो जो कर सकती है वो कर रही है लेकिन कनाडा की सरकार कुछ नहीं कर सकती. कनाडा के लोगों को खतरों से बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दुनिया में दोहरे मापदंड हैं। अगर अमेरिका कहीं हमला करता है तो हर कोई उसे सही कदम बताता है, लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो उसकी निंदा की जाती है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कनाडा ने भारत के साथ कुछ गलत किया है बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि कनाडाई सरकार ने कनाडाई लोगों को इस हिंसा से बचाने के लिए क्या किया है। कोई नहीं देख रहा है और किसी को परवाह नहीं है।

इस दौरान पत्रकार के इस सवाल पर कि अब कनाडा को क्या करना चाहिए, दोसांझ ने कहा कि कनाडा को खालिस्तान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्हें खालिस्तानियों को घृणा अपराध करने से रोकना चाहिए और कनाडा के मित्र देश के बारे में बयान देना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात दूसरे देशों में कभी नहीं हुए, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका। इतना ही नहीं, 1984 के बाद ऐसे हालात नहीं बने। ये समझ से परे है कि ऐसे हालात क्यों हैं। ब्राउन लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। बड़े-बड़े राजनेता कुछ नहीं कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं।

आपको बता दें कि आज एक ताजा घटना में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो के साथ अपने सीधे संबंध को स्वीकार किया है। पन्नू ने दावा किया कि वह पिछले तीन साल से टूडो के सीधे संपर्क में था और उसने भारत के खिलाफ जानकारी दी थी, जिस पर टूडो ने कार्रवाई की थी।

पिछले साल खालिस्तानी समर्थक निजहर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद सोमवार को कनाडा ने छह भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इस बीच कनाडाई चैनल सीबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में पन्नू ने कहा कि यह कार्रवाई उनके कहने पर की गई है।

जस्टिन टूडो का बड़ा कबूलनामा

निज्जर हत्याकांड में कनाडा के पास नहीं था भारत के खिलाफ कोई ठोस सबूत

ओटावा: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने बुधवार को स्वीकार किया कि जब उन्होंने पिछले साल खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निजर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ''ठोस सबूत नहीं था।

संघीय चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच के सिलसिले में टूडो ने गवाही देते समय यह बात कही। टूडो ने इस दौरान दावा किया कि भारतीय राजनयिक कनाडा के उन लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे जो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से असहमत हैं, और इसे भारत सरकार के उचतम स्तर और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जैसे आपराधिक संगठनों तक पहुंचा रहे थे।

टूडो ने कहा, ''मुझे इस तथ्य के बारे में जानकारी दी गई कि कनाडा और संभवत: 'फाइव आईज सहयोगियों से खुफिया जानकारी मिली है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत इसमें शामिल था...भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में शामिल थे।

कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐसी चीज है जिसे उनकी सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया। फाइव आईज नेटवर्क पांच देशों का एक खुफिया गठजोड़ है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। टूडो ने कहा, ''भारत ने वास्तव में ऐसा किया, और हमारे पास यह मानने के कारण हैं कि उन्होंने ऐसा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का तात्कालिक दृष्टिकोण भारत सरकार के साथ मिलकर इस पर काम करना है, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

सिंगापुर पुलिस ने एअर इंडिया विमान में बम को लेकर किया नया खुलासा

इंटरनेशनल डेस्क. सिंगापुर पुलिस ने एअर इंडिया विमान में बम को लेकर नया खुलासा किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बम होने की धमकी के बीच एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में जांच में कोई बम नहीं मिला। यह विमान अपने निर्धारित आगमन समय से एक घंटे से अधिक समय बाद सिंगापुर में उतरा। यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि भारतीय शहर मदुरै से आए किफायती एयरलाइन्स के विमान की चांगी हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद उसे कोई बम नहीं मिला। एयरलाइन को ई-मेल के माध्यम से मंगलवार रात आठ बजकर 50 मिनट पर सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर उतरने वाली उड़ान संख्या एएक्सबी684 में बम होने की सूचना मिली।

रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयर फोर्स के दो एफ-15 लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में यह विमान रात 10.04 बजे उतरा। 'द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि उन्हें रात 8.25 बजे बम की धमकी के बारे में सूचना मिली और विमान के उतरने के बाद उन्होंने जांच पूरी कर ली। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और जानबूझकर सार्वजनिक भय पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उड़ानों पर नजर रखने वाले 'फ्लाइटरडार24 ने दिखाया कि विमान उतरने से पहले सिंगापुर के पूर्वी क्षेत्र में लगभग एक घंटे तक चक्कर लगाता रहा। रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, हमारे आरएसएएफ के दो एफ-15एसजी विमानों ने विमान को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाकर सुरक्षित रूप से सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर आज रात लगभग 10.04 बजे उतारा।

हमारी जमीन स्थित आधारित वायु रक्षा प्रणालियां और विस्फोटक आयुध निस्तारण दल को भी सक्रिय किया गया था। उन्होंने बताया कि विमान के उतरते ही उसकी जांच का जिम्मा हवाई अड्डा पुलिस को सौंप दिया गया।

जयशंकर ने पाकिस्तान में चलाया पर्यावरण अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम' का लगाया पौधा

इस्लामाबाद। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहाँ वह 15-16 अक्टूबर को आयोजित दो दिवसीय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के नेता मौजूद हैं, और जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है। सम्मेलन के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ से मुलाकात की, जिन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके अलावा, जयशंकर ने पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग का भी दौरा किया और 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत अर्जुन का पौधा लगाया। पौधरोपण के दौरान उन्होंने खुद उसे खाद और पानी भी दिया। इस पहल की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा की।

यह अभियान भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और माताओं के सम्मान में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोग अपने माताओं के नाम पर पौधे लगाते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने का काम किया जा रहा है। जयशंकर ने न केवल पौधा लगाया, बल्कि उसे खाद और पानी भी दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह इस अभियान को व्यक्तिगत रूप से कितना महत्व देते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसकी तस्वीरें भी साझा की, जिसमें पौधरोपण की प्रक्रिया और संदेश को दिखाया गया है।यह दौरा दोनों देशों के बीच संवाद की एक महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग की आवश्यकता बढ़ गई है।

9 साल बाद यह पहला मौका है जब एक भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की है। इससे पहले 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। यह दौरा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए अहम है।यह सम्मेलन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। भारत और पाकिस्तान दोनों स्छ्ह के सदस्य हैं, और इस मंच पर विभिन्न क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस साल के सम्मेलन में आतंकवाद, सुरक्षा, व्यापार, और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जयशंकर ने भारतीय दृष्टिकोण को रखते हुए क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए भारत के योगदान की बात की।

जयशंकर की इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने जयशंकर का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर दोस्ताना माहौल का संकेत दिया। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत-पाकिस्तान के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में इस तरह की उच्च-स्तरीय मुलाकात से दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं।

भारत में 13 करोड़ लोग अभी भी गरीब

विश्व बैंक की रिपोर्ट में दी गई समस्या के समाधान की समयसीमा

नेशनल डेस्क। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में अभी भी लगभग 13 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। यह आंकड़ा 1990 में 43.1 करोड़ से घटकर 2024 में 12.9 करोड़ पर पहुंच गया है। हालांकि, यह आंकड़ा केवल 2.15 डॉलर प्रतिदिन के मानक पर आधारित है, जो कि वैश्विक स्तर पर अत्यंत गरीब माने जाने वाले लोगों की स्थिति को दर्शाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गरीबी रेखा का मानक विभिन्न देशों में भिन्न होता है। मध्यम-आय वाले देशों के लिए जो मानक 6.85 डॉलर प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार, 1990 की तुलना में 2024 में भारत में अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह, हालात में सुधार की बजाय स्थिति और भी विकट हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या इस समस्या का एक प्रमुख कारण है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और इसका सीधा असर गरीबी पर पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, विश्व बैंक ने भी कहा था कि 2021 में भारत में अत्यंत गरीब लोगों की संख्या 3.8 करोड़ घटकर 16.74 करोड़ हो गई थी। लेकिन इसके पूर्व के दो वर्षों में इस संख्या में वृद्धि देखी गई थी, जो चिंता का विषय है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अफ्रीका के सहारा क्षेत्र और अन्य विकासशील देशों में अत्यंत गरीबी की स्थिति और भी विकराल हो चुकी है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, जो उनकी जीवनशैली को प्रभावित कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी और प्लानेट- पाथवेज आउट ऑफ द पॉलिक्राइसिस शीर्षक के तहत, दुनिया में घनघोर गरीबी में कमी आने की रफ्तार ठहर गई है। मौजूदा गति से अगर गरीबी को कम किया जाता रहा, तो इसे समाप्त करने में कई दशक लग सकते हैं। इसके अलावा, रोजाना 6.85 डॉलर से ऊपर उठाने में एक शताब्दी से भी अधिक समय लग सकता है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि भारत सहित कई देशों को गरीबी की समस्या से निपटने के लिए ठोस और समग्र कदम उठाने की आवश्यकता है।

पिता के कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस बनी बेटी, 25 साल बाद खुद किया इंसाफ

इंटरनेशनल डेस्क. आम लोगों को कई बार इंसाफ पाने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है। न्याय में देरी के कारण लोग परेशान होकर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। हालांकि, बदला लेने का एक कानूनी तरीका भी है। एक लड़की ने अपने पिता के हत्यारे को पकड़ने के लिए 25 साल तक पुलिस बनी और अंतत: उसे जेल भेजने में सफल हुई। उत्तरी ब्राजील की गिस्लेने सिल्वा डी डेउस उस समय सिर्फ नौ साल की थीं, जब 1999 में उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गिस्लेने के पिता की जान महज 20 डॉलर के लिए ली गई थी और उनकी मौत ने गिस्लेने को गहरे सदमे में डाल दिया। हत्या के मामले में रेमुंडो अल्वेस गोम्स को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 2013 में कोर्ट ने उसे 12 साल की सजा सुनाई, लेकिन वह जल्दी ही जेल से बाहर आ गया। गिस्लेने ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस में शामिल होकर उस हत्यारे को पकड़ने का फैसला किया।

वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने आखिरकार उसे फिर से गिरफ्तार करवा लिया और उसे न्याय दिलाया। यह कहानी न केवल इंसाफ की लड़ाई की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि धैर्य और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। गिस्लेने सिल्वा ने अपने पिता के हत्यारे को जेल में रखने के लिए कई बार अपील की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 2016 में हत्यारे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। अपने पिता के हत्यारे को पकड़ने के लिए गिस्लेने ने वकील की नौकरी छोड़कर पुलिस में शामिल होने का निर्णय लिया और जेल की अधिकारी बन गईं। उनका लक्ष्य था कि हत्यारा उसी जेल में आए, जहां वह काम कर रही थीं। कड़ी मेहनत के बाद गिस्लेने अंतत: उस व्यक्ति तक पहुंच गईं, जिसने उनके पिता की हत्या की थी। जब उन्होंने उसे पकड़ा, तो वह भावुक हो गईं और रोते हुए कहा कि उन्हें लगने लगा था कि शायद वह कभी उस पल तक नहीं पहुंच पाएंगी। 25 साल बाद आखिरकार उन्हें अपने पिता के हत्यारे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। मीडिया से बात करते हुए गिस्लेने ने कहा- जब मैंने देखा कि मेरे पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अंतत: हथकड़ी पहना दी गई है, तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी। उनके आंसू राहत के थे, जो इस लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार मिले इंसाफ को दर्शा रहे थे। यह कहानी न केवल एक बेटी की संघर्ष की है, बल्कि यह दिखाती है कि मेहनत और समर्पण से इंसाफ भी मिल सकता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569